www.ghoonghatkibagawat www.ghoonghatkibagawat ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 35 गोरखपुर, 16 मार्च 2025 रविवार पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा

भारत और मॉरीशस के बीच संबंधों में मील का पत्थर साबित होगी

भारत ने हर संकट के समय मॉरीशस की सहायता की है। चाहे कोविड-१९ महामारी हो, वाकाशियो तेल रिसाव संकट हो या चक्रवात चिडो हो। भारत ने इन सभी चुनौतियों का सामना करने में मॉरीशस को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। 2023-24 में मॉरीशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था। 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत हुए। भारत की स-ार्वजनिक क्षेत्र की ग्यारह प्रमुख कंपनियां मॉरीशस में कार्यरत हैं जिनमें एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ऑयल (मॉरीशस) और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। मॉरीशस को भारत की तकनीकी शक्ति का लाभ मिल रहा है। 1986 में भारत और मॉरीशस के बीच उपग्रह ट्रैकिंग और कमांड स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था। एक नवम्बर,2023 को भारत और मॉरीशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच संयुक्त उपग्रह विकास के लिए समझौता हुआ।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यह उनकी दूसरी राजकीय यात्रा होगी। इससे पहले वह 2015में भी इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि रह चुके हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच विशेष और ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना का एक जहाज पोर्टलुई पहुंचेगा। साथ ही भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी, भारतीय वायु सेना की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम, नौसेना का हेलीकॉप्टर और एनसीसी कैडेटों की टीम भी समारोह में भाग लेगी।

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। साथ ही यह दोनों देशों के बीच मजबूत वित्तीय और व्यापारिक संपर्क को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक जन-से-जन संबंधों को और अधिक गहरा करने का अवसर भी प्रदान करेगी। भारत और मॉरीशस के बीच संबंध केवल कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इन मजबूत संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

यह यात्रा भारत और मॉरीशस के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास होगी। भारत और मॉरीशस कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं: समुद्री सुरक्षा, विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग, संस्कृति एवं जन-से-जन संपर्क। भारत ने मॉरीशस में कई मह'वपूर्ण विकास परियोजनाओं में भागीदारी की है।

2016 में भारत ने 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया, जिससे मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, नये अस्पताल, सामाजिक आवास परियोजना और स्कूल के बच्चों के लिए डिजिटल टैबलेट्स जैसी परियोजनाओं को वित्तझ पोषित किया गया।

2017 में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी गई, जिससे मेट्रो प्रोजेक्ट (फेज और), फायर-फाइटिंग वाहन,सौर ऊर्जा संयंत्र, फॉरें-सिक साइंस लैब, राष्ट्रीय अभिलेखागार और मॉरीशस पुलिस अकादमी जैसी दस परियोजनाओं को वित्त-पोषित किया गया। जनवरी, 2022 में 96 सामुदायिक विकास परियोजनाओं की योजना बनाई गई, जिनमें से 51 परियोजनाओं का उद्घाटन हो चुका है।

मॉरीशस की 1.3 मिलियन जनसंख्या में 70 फीसदी भारतीय मूल के लोग हैं। 1976 में स्थापित महात्मा गांधी संस्थान भारत-मॉरीशस के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। मॉरीशस में स्थित विश्व हिन्दी सचिवालय हिन्दी भाषा के वैश्विक प्रचार के लिए भारत और मॉरीशस की एक संयुक्त पहल है। 1987 में स्थापित इंदिरा गांधी भारतीय संस्कृति केंद्र विदेश स्थित भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। ओसीआई कार्ड के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे मॉरीशस के भारतीय मूल के नागरिक अपनी ७वीं पीढ़ी तक भारतीय मूल का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

मॉरीशस भारत के शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है जिसके तहत 2002 से अब तक 4940 मॉरीशस के नागरिकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

इंडिया-अफ्रीका मैत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 60 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। प्रत्येक वर्ष। लगभग 200 मॉरीशस के छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में स्वयं वित्त-पोषित पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं। वर्तमान में 2300 भारतीय छात्र मॉरीशस में विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, होटल प्रबंधन और व्यवसाय अध्ययन में पढ़ाई कर रहे हैं।

मॉरीशस ने 2004 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त व्यवस्था शुरू की जिससे भारतीय पर्यटक एक महीने तक बिना वीजा के मॉरीशस जा सकते हैं। भारत भी मॉरीशस के नागरिकों को निःशुल्क वीजा प्रदान करता है। कोविड-19 से पहले हर साल 80 हजार भारतीय पर्यटक मॉरीशस जाते थे और तीस हजार मॉरीशस के नागरिक भारत आते थे। यह संख्या अब फिर से बढ़ रही है।

सड़क दुर्घटनाओं की चिंता

मुख्यमंत्री ने मार्ग दुर्घटनाओं के ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के भी निर्देश दिए और कहा कि यह भी देखना होगा कि वर्ष 2024 में प्रवेश में 45 जिलों में से 42 प्रतिशत दुर्घटनाएं 20 जिलों हो हुई। को मिले हैं - हरदोई, मथुरा, आगरा, लखनऊ बुलंदशहर, कानपुर (नगर), प्रयाग राज सीतापुर उन्नाव बाराबंकी लखीमपुर खीरी बरेली, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कुशीनगर बदायूं मेरठ और बिजनौर में जान हानि हुई है। सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु में 42 प्रतिशत मौतें इन्हीं जनपदों में हुई हैं। मार्ग दुर्घटनाओं कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि - ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्र150 गलत साइड पर गाड़ी चलाना जॉपिंग रेड लाइट एवं मोबाइल फोन का उपयोग प्रमुख रूप से है। शराब पीकर लोग गाड़ी न चला सकें इसके लिए एक्सप्रेस वे पर शराब बिक्री रोकने के आदेश दिए गए हैं। शराब की दुकानों के साइनेज बहुत बड़े होने की बजाय छोटे होने चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और मौतों की संख्या बढ़ी है। वह बेहद चिंताजनक है। दुर्घटनाएं सिर्फ आप पर निर्भर नहीं करती है। लेन ड्राइविंग में भी कौन कब कब कहां से अचानक डिवाइडर पार करके पिकल आएगा। कौन सी गाड़ी उल्टी दिशा में तीव्र रफ्तार से आने वाली आपसे भिड़ जाएगी। कौन सी ट्रक, ट्रालर खराब खराब होकर या यूं ही सड़क पर खड़ी रहकर आने वाली गाड़ियों को दुर्घटनाओं की दावत देती रहेगी। नहीं कहा जा सकता है। वहीं आवारा पशु, वन्य जीव भी सड़कों पर दुर्घटना का कारण बनते जा रहे हैं। पहले कभी-कभार लोग नील गाय से टकरा जाते थे। जब वे अचानक सामने से आ जाते थे। अब, आवारा पशु वो इन सड़कों पर बैठ कर ही आराम से जुगाली कर रहे होते हैं। या युद्ध कर रहे होते हैं। आप यदि सतर्क होते हैं तो दुर्घटना होनी ही है। प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने राज्य सड़क सुरक्षा, परिषद की बैठक में दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि-यह अत्यंत दुखद है कि- 2024 में प्रदेश में 46052 दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें 34600 लोग घायल हुए और 24 हजार से ज्यादा मौतें हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी एक्सप्रेस वे पर दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए ताकि दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल इलाज मिल सके। उन्होंने मंडल के मुख्यालयों के अस्पतालों में ट्रामा सेंटर, एंबुलेंस एवं ट्रेंड स्टाफ की तैनाती भी सुनिश्चित करने के लिए कहा। गाडियों की तेज रफ्तार और चौड़ी सड़कों ने लोगों की रफ्तार तेजी से बढ़ा दी। गाडियों की बढ़ती स्पीड और सड़क रफ्तार को पंख लगा लिए हैं। हर आदमी जल्दी पहुंचने की होड़ में शामिल है। वह चाहे दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन सड़क पर चलने वालों को ड्राइविंग का सलीका तक नही पता है। जो ड्राइवर साहबान किसी बड़े साहब या किसी राजनेता की गाड़ी तला रहे है। तो फिर क्या कहने। उनकी तो पौ बारह... इसलिए दुर्घटनाओं के लिए जो कारण मुख्य मंत्री ने गिनाए। वह वहीं तक सीमित नहीं है। सड़कों के किनारे शराब पीकर गाड़ी न चलाएं का बोर्ड लगा देने मात्र से न लोग शराब पीना छोड़ देंगे और ना ही शराब पीकर गाड़ी चलाना छोड़ सकते हैं। एक ओर तो सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए सभी को शराब पिलाने पर तुली हुई है। वहीं दूसरी ओर कह रही है की एक्सप्रेस वे पर शराब नहीं बिकेगी लेकिन इसका सेवन करने वाले अपना इंतजाम करके चलते हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कों को आम जनता जो इसके आस-पास निवास करती है। खेती किसानी करती है की सुविधाओं का ध्यान बिल्कुल ही नहीं रखा गया है जिसका परिणाम है कि लोग गलत तरीके से कट बनाते हैं और उसे इस्तेमाल करने को मजबूर होते हैं। इसे वजह से सड़क पार करने के दौरान ही बहुत सी दुर्घटनाएं होती है जिनमें न सिर्फ गाड़ी वाले लोग प्रभावित होते हैं बल्कि पैदल चल रहे या सड़क पार कर रहे लोग भी इसके शिकार होते हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिन 20 जनपदों की खोज की गई है वहां कुल दुर्घटनाओं की 42 फीसदी मौतें इन दुर्घटनाओं में हो रही है उनका अध्ययन कराया जाना चाहिए कि आखिर किन कारणों से ऐसा हो रहा है। सड़क के किनारे यह लिख देने मात्र से कि 'दुर्घटना बहुल क्षेत्र है' दुर्घटनाएं नहीं रुकने वाली है। इसके लिए सड़क की बनावट को भी देखा जाना चाहिए और बस्तियों के आस-पास की सड़कों तक पहुंच मार्ग भी होने चाहिए जिससे लोगों के दैनंदिन खेती किसानी के कार्यों में भी व्यवधान न पड़े और उनके लिए ही नहीं जो पैदल चलने वाले हैं साइकिल चलाने वाले हैं, उनके लिए भी सड़क पर जगह होनी ही चाहिए।

पाकिस्तान कैसे निपटेगा बलूचिस्तान से

ऐसा दावा कि-पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दो दर्जन बलूच लड़ाकों को मार गिराया है और एक सैकडा से अधिक बंधकों को छुड़ा लिया है। दिलचस्प बात यह कि बलूच लड़ाकों की कैद से अपने बंधकों को आजाद कराने में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज कितनी कामयाब साबित होती हैं लेकिन वास्तविक प्रश्न यह किं- बलूचिस्तान में आने वाली अतंकवाद की लपटों से पाकिस्तान कैसे निपटेगा जिस तरह बलूच की डोर उसके हाथों से निकलती जारही है। उससे तो यह प्रतीत होता है कि आगामी वर्षों में बलुचिस्तान अपनी आजादी की जंग में कामयाब होगा। ऐसा इसलिए कि-पाकिस्तान में चौतरफा अराजकता का माहौल है। खैबर पख्तूनवां में भी आग लगी है। सिंध प्रांत भी उबल रहा है। पाकिस्तान की भूमि पर फन फैलाए बैठे आतंकी संगठन भी अब पाकिस्तानी संप्रभुता के लिए नई चुनौती परोस रहे हैं। फिर बलूचिस्तान कब-तक पाकिस्तान का अविभाजित अंग बना रहेगा। जानना आवश्यक है कि बलूचिस्तान तेल और खनिज से सम्पन्न पाकिस्तान का सबसे बड़ा कम आनेवाला राज्य है। जहां सर्वाधिक आबादी बलूचों की है और उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार उनके साथ भेद-भाव और उनका शोषण करती है। उनके खनिज संपदा का जमकर दोहन करती है लेकिन उनकी बुनियादी जरूरतों का तनिक भी ख्याल नहीं रखती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि राजानीतिक तौर पर बलूचों के साथगेद भाव नाइंसाफी और शोषण ने वहां के लोगों के मन में पाकिस्तानी सर भार के खिलाफ, नफरत का भाव भर दिया है। पाकिस्तान के अस्थिर बलुचिस्तान राज्य में स्वाधीनता की जंग लड़ रहे बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएनए) के सदस्यों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर पाकिस्तानी हुकूमत के माथे पर शिकन ला दी यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। तभी बलून लड़ाकों ने इसे बंधक बना लिया। बंधक बनाए गए लोगों में सर्वाधिक पाकिस्तानी आर्मी और और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ही लोग हैं। लड़ाकों की मानें तो उन्होंने आम नागरिकों को आजाद कर दिया है। तकरीबन तीस सैनिकों की हत्या की बात कबूली है। बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने कहा है कि वे सैनिकों को रिहा नहीं करेंगे। दर असल उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें पाकिस्तान को सरकार पूरा करती है तो बंधकों की जान बख्श सकते हैं। लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर लाशों से भरी ट्रेन को पाकिस्तान की सरकार को मिलेगी। बलुच लिबरेशन आर्मी की मांग है कि पाकिस्तान सरकार बलूच के राजनीतिक कैदियों अब हुए लोगों, अलगाववादी नेता ओ लड़ाको और उनके कार्यकताओं को बिना किसी शर्त के रिहा करो वर्ना उन्हें खतरनाक परिणाम भुगतना पड़ेगा। लड़ाकों ने पाकिस्तान की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उधर पाकिस्तान की सरकार भी बंधकों को छुड़ाने के लिए कसरत कर रही है।

गौरतलब है कि -पाकिस्तान सेना दशकों से बलुचिस्तान में अलगाववादियों का उत्पीडन व हत्या कर रहे है। अब तक पाकिस्तानी सेना के हाथों हाबारों बलूच नागरिक भोरे जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना द्वारा 2006 में में बलोच ने नवाब अकबर चुगती की हत्या के बाद बलियो अगातार पहने से बढ़ गया है। स्माणोय है कि 2005 में अकबर बुगती और भीर बलात मारी (मीर बलात मारी) द्वारा पाकिस्तान सरकार के सामने 15 सूत्रीय मांगें रखी गई थी। इस मांग में बलुचिस्तान प्रांत के संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण और सैनिक ठिकानों के निर्माण पर रोक का मुद्दा शीर्ष पर था लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप टकराव बढ़ गया, जबकि हकीकत है कि बलुचिस्तान के नागरिक अलगाववादी नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से लैस है। पाकिस्तान के कुल प्राकृतिक गैस का एक तिहाई इसी से निकलता है। लेकिन विडंबना है कि उसका आनुपातिक लाभ बलुचिस्तान को नहीं मिलता है। उदाहरणार्थ-1952 में बलुचिस्तान के डेरा बुगती में गैस के भंडार का पता लगा और 1954 से गैस का उत्पादन शुरू हो गया।

पाकिस्तान के अन्य तीनों प्रांतों को उसका लाभ तुरन्त मिलने लगा, लेकिन बलुचिस्तान को यह लाभ 1985 में मिला। इसी तरह चीन के साथ तांबा, सोना और चांदी उत्पादन करने को तगाई मरुस्थल योजना 2002 में आकार ली तय हुआ कि बलुचिस्तान को इसका वाजिब लाभ मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस योजना के तहत प्राप्त लाभ में चीन का हिस्सा 75 फीसद और पाकिस्तान का 25 फीसद है लेकिन इस 25 फीसद में बलूचिस्तान के हिस्से सिर्फ 2 फीसद ही आता है। यह स्थिति तब है जब पाकिस्तानी संविधान के 18वें संशोधन के मुताबिक बलुचिस्तान को विशेष अधिकार प्राप्त है। उसी नाइंसाफी का नतीजा है कि बलुचिस्तान के नागरिक आक्रोशित है और पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि बलुचिस्तान कभी पाकिस्तान का नैसर्गिक हिस्सा नही रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो यह पाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ ही बलुचिस्तान ने भी अपनी आजादी की घोषणा की थी। लेकिन अप्रैल, 1948 में मीर अहमद यार खान को पाकिस्तान को सेना ने अपना राज्य क्लांत को छोड़ने को मजबूर कर दिया था उससे जबरन कलात की आजादी के खिलाफ समझौते पर हस्ताक्षर करवाया गया था जबकि उनके भाई प्रिंस अब्दुल करीम खान इस समझौते के खिलाफ थे। वे किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान का 23 फीसद हिस्सा पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं थे। लिहाजा उन्होंने 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ अलगाव का बिगुल फूंक दिया। उनके नेतृत्व में बलूच नागरिकों ने अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के सैनिकों के खिलाफ गुरिल्ला जंग छेड़ दिया। इस संघर्ष को नवाब नवरोज खान ने आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी कीमत उन्हें भारी चुकानी पड़ी। पाकिस्तान की सरकार ने उनके दोनो बेटों और भतीजों को फांसी पर लटका दिया। इस अत्याचार के बाद भी जब बलूचों का स्वर धीमा नहीं पड़ा तो यहां 1973-74 में मार्शल-लॉ लागू कर दिया गया और अलगाववादियों के विरुद्ध दमनात्मक कारवाई शुरू हो गई। इस दौरान तकरीबन आठ हजार बलूची नागरिक मारे गए, हजारों घायल हुए लेकिन गौर करें तो पाकिस्तानी सेना के जुल्म के बाद भी आजादी का स्वर थमा नहीं है। मौजूदा समय में बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलूच आर्मी, लश्कर ए बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट जैसे संगठन बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलित हैं। पाकिस्तान के लिए यह मुसीबत पैदा करने वाला है कि भारत ही नहीं अमेरिका भी बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना द्वारा मानवाधिकार हनन और अत्याचारपूर्ण कार्रवाई का अनैतिक मान रहा है। स्मरणीय है कि गत वर्ष पहले कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन सांसद दाना रोहराबचेर ने दो अन्य स-ांसदों के समर्थन से अमेरिकी कांग्रेस में बलूचिस्तान के लोगों के लिए इन जुल्मों के खिलाफ 'अत्मनिर्णयन' के अधिकार की मांग वाला प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि बलूचिस्तान का प्रदेश पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है और यहां के लोगों को संप्रभु अधिकार प्राप्त नहीं है। याद होगा वर्ष 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाए जाने से पाकिस्तान घिर गया था। तब उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे इतना करारा झटका लगा था कि वह निर्वासित बलूच नेताओं से बातचीत को तैयार हो गया था। तब बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री नवाब सनाउल्लाह जेहरी और पाकिस्तानी सेना के दक्षिणी कमान के कमांडर आमिर रियाज ने बलूच नेताओं से बातचीत का पैगाम भेजा। तब बलूच नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री के समर्थन से उत्साहित होकर भारत का शुक्रिया जताया था। दो राय नहीं कि आने वाले दिनों दुनिया के अन्य देश भी बलूचिस्तान के मसले पूर मुखर होगें और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेगी।

डिजिटल लेन-देन में यूपी नंबर -वन

आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। कर अपवंचन को रोका गया है। रेवेन्यू लीकेज को समाप्त किया गया है बीते आठ वर्षों में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम है बावजूद इसके उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। आज टैक्स का इस्तेमाल जनता के हित में हो रहा है। जैसे-हाईवे बने, पुल बने, स्कूल-कॉलेज बने, अस्पताल बने हैं। प्रदेश 400 लाख टन सबज़ियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में माह दिसंबर तक 28.58 लाख कृषकों द्वारा 19.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल बीमा कराया गया है और 9.33 लाख बीमित कृषकों को 495.41 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। डिजिटल क्रांति का सर्वश्रेठ उदाहरण बनकर उभरा है। देश 2017-18 में अवधि में जहां 122.84 करोड डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे। वहीं-2024-25 में दिसंबर- 2024 तक 1024.41 करोड डिजिटल ट्रांजेक्शन हो चुके हैं।

यू पी आज डिजिटल लेनदेन में अपनाने में नंबर एक है। आधे से अधिक लेन-देन यू पी आई से हुए। इसकी वजह डिजिटल बैंकिंग की आसान पहुंच, गांवों तक इंटरनेट, वित्तीय जागरुकता और उपकरणों की पर्याप्त संख्या है। आज देश में बैंकों की 20416 शाखाओं, 4.00, 932 बैंक मित्र एवं बीसी सखी, 18,744 एटीएम और 4,40.095 बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जारी है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और बेईमानी पर कठोर प्रहार कर रही है।

11 विभागों की 207 योजनाओं की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। उसमें 113 केन्द्रीय योजनाएं और 11 राज्य सेक्टर की योजनाएं हैं।

डी बीती से करोड़ 08 लाख से अधिक लोगों को 1 लाख 11 हजार 637 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। इससे प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। अप्रैल 2000 से जून-2017 तक है, 303 करोड़ रुपए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) के जरिए यूपी को मिले। वहीं अप्रैल-2017 से सितंबर 2024 तक 14 हजार 8 करोड़ रुपए से अचिता आया है। जो गह बताता है कि- प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

धर्म-दर्शन, कला, विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कई शताब्दियों तक विश्व के मानचित्र पर चमकता रहा है। राम कृष्ण का अवतार भी इस भूमि पर हुआ है। अनादिकाल से काशी भी शिव की आराधना का केन्द्र रही है। भगवान बुद्ध और महावीर की भी उत्तर प्रदेश कर्म भूमि रही है। प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से उत्तर प्रदेश कभी पिछड़ा प्रदेश नहीं रहा है। नीति आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति एके संबंधित से प्रकाशित रिपोर्ट में में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष.. 2018 से 19 वर्ष-2023-23 की अवधि में पदेश के समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का इजाफा हुआ। व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है, वर्ष-2018-23 की अवधि में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है।

देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष-2022-2023, 2023-24, 2024 एवं 2024-25 में क्रमशः 9.5 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत एवं 11.5 प्रतिशत रहा जो महाराष्ट्र के उपरान्त देश में सर्वाधिक हैं। उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष व्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 एवं 12.1 प्रतिशत रहा जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत- 10.3, 9.4. एवं 8.9 रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 और 7.2 प्रतिशत रहा, जब कि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 और 10 प्रतिशत रहा।

आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं है। वे चाहे जहां जाएं। 6 साल में पांच लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक विकास की इकाइयां स्थापित की गईं। इनमें कई में प्रोडक्शन हो रहा है।

बेरोजगारी दर जो 2016 में 18 फीसदी थी वह आज 3 से 4 फीसदी है, जितना गन्ना मूल्य भुगतान 2007 से 2017 के बीच में हुआ इसका दोगुना सरकार ने 2014 के बाद किया। सरकार दो लाख दो हजार करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान कर चुकी है। वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी को वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52.271 रुपए थी।

वर्ष-2023-24 में 93.514 रुपए है। 2016-17 में कुल राजस्व, प्राप्तियां दो लाख 56 हजार रुपए हुई थी। जबकि, चालू वित्तीय वर्ष के जनवरी माह तक ही चार लाख दस हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

क्या अब यूनुस को लेकर लोगों का भ्रम टूटेगा?

बांग्लादेश में तमाम कारखाने बंद हो गए हैं। नतीजतन अनेक स्त्री-पुरुष बेकार घूम रहे हैं। बेरोजगार पुरुष चोरी-डकैती तो मजबूर औरतें वेश्यावृत्ति कर रही हैं। ऐसे में मजहब के कारोबारी मजे में हैं। यही एक धंधा है, जो खूब चल रहा है। इसके साथ-साथ देश में कट्टरता बढ़ रही है। पूरा बांग्लादेश डरा हुआ है। सजग लोग अगर अब भी खड़े नहीं हुए, तो बांग्लादेश रसातल में जाता रहेगा, जलता रहेगा और यूनुस साहब हंसते रहेंगे। वह सत्तालोभी, स्वार्थी, अनुदार, ईर्ष्यालु, क्रूर व्यक्ति हैं। नोबेल पुरस्कार से उन्होंने सम्मान पाया था, लेकिन बांग्लादेश की सत्ता का संचालन करते हुए वह निंदा के पात्र बन चुके हैं। वह बांग्लादेश में कट्टरता, हिंसा, चोरी, डकैती और दुष्कर्म पर अंकुश लगाने के जरा भी इच्छुक नहीं दिखते।

सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था कि यूनुस का संबंध किसी भी तरह जमाते इस्लामी से हो सकता है, क्योंकि वह मुक्तियुद्ध विरोधी है और 1971 में बांग्लादेश को मिली आजादी नहीं चाहता था। वह पाकिस्तानपरस्त और भारत विद्वेषी है। मेरे जैसे असंख्य लोगों ने यूनुस की छवि शांति चाहने वाले व्यक्ति की बना रखी थी। जिस व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका हो, वह शांतिप्रिय नहीं होगा, तो भला कौन होगा, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने भारत-विरोधी रुख अपनाना शुरू कर दिया। फिर वह बांग्लादेश के इतिहास को पूरी तरह खारिज करने के अभियान में लग गए।

अगर यूनुस भले आदमी होते, तो सत्ता में आते ही सबसे पहले चुनाव आयोजित कराने के बारे में सोचते और नेताओं को जिम्मेदारी सौंपकर अपना पद छोड़ देते, क्योंकि उनका क्षेत्र राजनीति नहीं है, लेकिन 84 साल की उम्र में भी वह बांग्लादेश को नष्ट करने के अपने अभियान में लगे हैं।

अवामी लीग के नेताओं-कार्यकताओं को खत्म करने की मंशा से उन्होंने आपरेशन डेविल हंट नाम से एक अभियान शुरू किया। अवामी लीग के छात्र संगठन पर उन्होंने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। अब अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह मिटा देने का उनका इरादा है।

अवामी लीग के सभी नेताओं-कार्यकताओं को या तो यूनुस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा या फिर उन्हें मिटा दिया जाएगा। जिहादी तत्वों को उन्होंने इस मुहिम में लगा दिया है।

यूनुस के अनुसार, नए बांग्लादेश का निर्माण अवामी लीग को खत्म किए बिना संभव नहीं। यूनुस जो कुछ करना चाहते हैं, जिहादी तत्व उन्हें वह सब मुहैया करा रहे हैं। दूसरी तरफ, जिहादियों को जो कुछ चाहिए, यूनुस उन्हें वह सब मुहैया करा रहे हैं।

यह अलग बात है कि बीच-बीच में वह कुछ ऐसे बयान भी दे रहे हैं, जिनसे जनता उन्हें भलामानुष समझे। जिहादियों को किसी बात की चिंता नहीं है। वे सिर्फ तोड़ना और नष्ट करना जानते हैं। उनकी मंशा प्रकाशकों पर हमला करने की थी, तो उन्हें वह मौका उपलब्ध कराया गया। वे पुस्तक मेले में स्टाल बंद करना चाहते थे तो उन्हें हरी झंडी दी गई। महिलाएं सैनिटरी नैपकिन की दुकान चला रही थीं। जिहादी उसे बंद कराना चाहते थे तो वह बंद करा दी गईं। जिहादी वैलेंटाइन डे पर फूलों की दुकान पर हमला करना चाहते थे। वे इसमें सफल रहे। मकर संक्रांति पर आयोजित पतंग उत्सव बंद करने के लिए उन्होंने सुनियोजित ढंग से पतंगों की दुकानों पर धावा बोला। जिहादी देश भर में आयोजित होने वाला वसंत उत्सव खत्म करना चाहते थे, सरकार ने उनकी मदद की।

लालन फकीर की स्मृति में आयोजित होने वाले उत्सव को भी उन्होंने बंद करा दिया। नाट्य उत्सव पर भी उनका हमला सफल रहा। इसके पहले जिहादियों ने 1971 के मुक्तियुद्ध से जुड़े तमाम स्मारकों और संग्रहालयों पर हथौड़ा चलाने की इजाजत मांगी तो वह भी उन्हें मिल गई।

बांग्लादेश में छात्रों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है। भले ही ये छात्र अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से अलग राह पर चलते दिखते हों, लेकिन उनकी पीठ पर उनका ही हाथ है। इस पार्टी में उनके अपने लोग हैं।

यूनुस की ऐसी हार्दिक अभिलाषा है कि चुनाव में यही पार्टी जीते। यदि ऐसा होता है तो देश के अनुभवी राजनेता हाथ मलते रह जाएंगे और यूनुस प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से सत्ता में बने रहेंगे। क्या अब यूनुस को लेकर लोगों का भ्रम टूटेगा? यूनुस ने प्रमाणित कर दिया कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले लोग भी कितने अनुदार हो सकते हैं।

वह नए सिरे से देश का संविधान बना रहे हैं। संविधान से पंथनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्ताव है। कट्टरवादी पार्टी जमाते इस्लामी के छात्र संगठन शिबिर के छात्रों ने उन्हें सत्ता में लाकर बिठाया। ये वे लोग थे, जो विगत जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन में नेपथ्य में थे। शिक्षा परिसरों में लंबे समय से इन्होंने प्रगतिशीलों की हत्या की है। हसीना को सत्ता से हटाने के लिए छेड़े गए छात्रों के आंदोलन की मदद हिजबुत तहरीर नामक आतंकी संगठन ने की थी।

बांग्लादेश में जारी ध्वंस पर विराम के लिए लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पक्षधर शक्तियों को परस्पर सहानुभूतिशील होना पड़ेगा। यह याद रखना होगा कि अशुभ शक्तियों को परास्त करने और बांग्लादेश को उसके शिकंजे से मुक्त करने के लिए अपने तुच्छ हितों को भूलकर मुक्तियुद्ध के पक्ष में लड़ने वाली तमाम शुभ शक्तियों को एकजुट होना पड़ेगा। बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक बदलाव हो गया, लेकिन उसका सुफल नहीं मिला। असल में हसीना और यूनुस में चौंकाने वाली समानताएं हैं। हसीना सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थीं। यूनुस भी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। हसीना बदला लेने से कभी नहीं चूकतीं थीं। यूनुस का भी यही स्वभाव है। हसीना जब सत्ता में थीं, तब तमाम गलतियों का ठीकरा विपक्षी दल बीएनपी पर फोड़ती थीं।

ठीक इसी तरह बांग्लादेश में आज जो कुछ भी गलत हो रहा है, यूनुस उस सबके लिए शेख हसीना और अवामी लीग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शेख हसीना इस्लामी कट्टरवादियों का तुष्टीकरण करती थीं। यूनुस भी उनके साथ खड़े हैं। हसीना के समय प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन मीडिया उनके स्तुतिगान में लगा रहता था। यही यूनुस चाहते हैं। हसीना भी मुझे बांग्लादेश नहीं आने देना चाहती थीं। यूनुस भी यही चाहते हैं।

बांग्लादेश में तमाम कारखाने बंद हो गए हैं। नतीजतन अनेक स्त्री-पुरुष बेकार घूम रहे हैं। बेरोजगार पुरुष चोरी-डकैती तो मजबूर औरतें वेश्यावृत्ति कर रही हैं। ऐसे में मजहब के कारोबारी मजे में हैं। यही एक धंधा है, जो खूब चल रहा है। इसके साथ-साथ देश में कट्टरता बढ़ रही है। पूरा बांग्लादेश डरा हुआ है। सजग लोग अगर अब भी खड़े नहीं हुए, तो बांग्लादेश रसातल में जाता रहेगा, जलता रहेगा और यूनुस साहब हंसते रहेंगे। वह सत्तालोभी, स्वार्थी, अनुदार, ईर्ष्यालु, क्रूर व्यक्ति हैं। नोबेल पुरस्कार से उन्होंने सम्मान पाया था, लेकिन बांग्लादेश की सत्ता का संचालन करते हुए वह निंदा के पात्र बन चुके हैं। वह बांग्लादेश में कट्टरता, हिंसा, चोरी, डकैती और दुष्कर्म पर अंकुश लगाने के जरा भी इच्छुक नहीं दिखते।

भारत के शैक्षणिक केन्द्र दुनिया के छात्रों के लिए आकर्षण का केन्द्र

भारत के शैक्षणिक संस्थान न केवल दक्षिण एशिया और अफ्रीका, बल्कि विश्व भर के छात्रों के लिए आकर्षक केंद्र हैं। ये छात्र यहां शिक्षा प्राप्त कर अपने देशों के उच्च पदों पर पहुंचते हैं और दीर्घकालिक रूप से भारत के साथ मजबूत राजनयिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के वाहक बनते हैं। भारत की ह्यसाफ्ट पावरह्न को भी सुदृढ़ करते हैं, लेकिन ऐसी त्रासद घटनाएं भारत की वैश्विक शैक्षणिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं और इसके भू-राजनीतिक प्रभाव भी होते हैं। नेपाली छात्रा की दुखद मृत्यु एक चेतावनी है कि भारत अपने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा, प्रशासनिक संवेदनशीलता और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को प्राथमिकता दे। एक समावेशी और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण न केवल भारतीय छात्रों, बल्कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी आवश्यक है, जो भारत को अपनी शिक्षा और भविष्य के निर्माण के लिए चुनते हैं। इस दिशा में दो महत्वपूर्ण सुधार अनिवार्य हैं-पहला, एक उत्तरदायी और संवेदनशील प्रशासनिक तंत्र, जो छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुने और उनका समाधान करे। दूसरा, चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना, ताकि किसी भी अप्रत्याशित संकट का समय रहते सामना किया जा सके। केवल इसी तरह हम भारत को एक वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में मजबूत कर सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बना सकते हैं।

ओडिशा स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलाजी (केआईआईटी) में नेपाली छात्रा की असामयिक मृत्यु न केवल दुखद और संवेदनशील मामला है, बल्कि यह भारत की शैक्षणिक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। केंद्र सरकार ने इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है और पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया है। इसके बाद करीब 1000 नेपाली छात्र केआईआईटी वापस लौटे हैं, लेकिन यह मामला केवल न्यायिक जांच तक सीमित नहीं रह सकता। इसके दो पहलू हैं, जिन पर भारत के नीति-निमार्ताओं को विचार करने की आवश्यकता है। पहला, नेपाल बीते वर्षों में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बदल चुका है।

भारत को इन बदलावों का संवेदनशीलता से आकलन करना होगा। दूसरा, यदि भारत को दक्षिण एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाना है तो अंतरराष्ट्रीय छात्रों, विशेषकर अपने पड़ोसी और मित्र देशों के विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित, संवेदनशील और समावेशी शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना होगा। इस तरह की घटनाएं इन देशों के साथ हमारे रिश्तों में

दरार पैदा कर सकती हैं। चीन जैसे देश जो लंबे समय से नेपाली युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अवसरों का उपयोग भारत की छवि को कमजोर करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि भारत अपने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और समावेशिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। साथ ही नस्ली, लैंगिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को संस्थागत ढांचे का अभिन्न अंग बनाए, ताकि सभी छात्र भयमुक्त माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें।

नेपाल भारत का एक खास पड़ोसी देश है। वह चाहे एक साझा संस्कृति की बात हो या सामाजिक और धार्मिक समानता, भाषा की या फिर लोगों के बीच आपसी संबंध की। भारत और नेपाल के बीच सामरिक ही नहीं, बल्कि एक मजबूत साझा सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक, सैन्य, शिक्षा, खुली सीमा और लोगों के बीच पारस्परिक संबंध हैं।

शायद यही कारण रहा है कि संबंधों में यदा-कदा मन मुटाव के बावजूद बातचीत का माहौल हमेशा से बना रहा है। पिछले दो दशकों में नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं। इसके चलते नेपाल एक संवेदनशील देश बन चुका है। इसका असर भारत-नेपाल संबंधों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम इस प्रयास में हैं कि चीन जैसी ताकत नेपाल के रास्ते भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान न कर सके।

एक समय था जब नेपाली छात्रों और कामगारों के लिए भारत ही प्रमुख गंतव्य हुआ करता था। खुली सीमा के कारण भारत आना-जाना न केवल आसान, बल्कि किफायती भी था। भारत सरकार की छात्रवृत्तियां नेपाली विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर खोलती थीं, लेकिन बीते दो-तीन दशकों में यह स्थिति काफी बदल गई है।

विशेष रूप से 1996 से 2006 तक चले माओवादी आंदोलन ने नेपाल के राजनीतिक सोच और विदेश नीति को नया स्वरूप दिया है। इसके साथ नेपाल में विदेश में रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करने वाली एजेंसियों का उदय हुआ है। एक समय जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पूर्वांचल विश्वविद्यालय नेपाली छात्रों के गढ़ माने जाते थे, जिसने भारत के प्रति नेपाल में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद की, लेकिन अब वह बदल चुका है। यह बदलाव केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी दिखता है। आज अधिकांश नेपाली विकसित देशों को लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे में भारत के प्रति जनता की राय में बदलाव आया है। इसका बड़ा फायदा चीन उठा रहा है, जो नेपाली छात्रों को लुभाने में लगा है। इसके परिणामस्वरूप भारत और नेपाल के बीच कोई भी राजनीतिक विवाद अब तुरंत इंटरनेट मीडिया पर छा जाता है।

गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों से वंचित होता आमजन

हमारे देश में त्योहारों का खासा महत्व है। त्योहारों की पहचान विशेष खाद्य पदार्थों से जुड़ी होती है, इस लिए त्योहारों के समय खाद्य पदार्थों की मांग अधिक होती है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री बाजारों में तेजी से होती है। बाजार में बिकने वाले कई ऐसे पदार्थ हैं जिनकी पहचान कर पाना आमजन के लिए बड़ी मुश्किल होता है। बाजारों में बिकने वाले घी, खोवा, विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और पनीर में सबसे अधिक मिलावट होती है। होली और रमजान को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-बड़े खाद्य विक्रेताओं के खाद्य पदार्थ का सैंपल एकत्रित कर रही हैं, शहर के विभिन्न क्षेत्रों से घी,खोया, पनीर, सरसों तेल, दूध और मिठाई जैसे खाद्य पदार्थों के सैंपल सबसे ज्यादा एकत्रित किए जा रहे हैं क्योंकि इनमें मिलावट सबसे अधिक होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटना कोई नई नहीं है। सभी राज्यों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें अक्सर त्योहारों के समय ही सुनने को मिलती हैं क्योंकि सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा त्योहारों के समय नकली और मिलावट खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जाती है।

नकली और मिलावट खाद्य पदार्थ बाजारों में सस्ती कीमत पर उपलब्ध होते हैं। इसलिए उपभोक्ता इनकी तरफ सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री के पीछे कई कारण हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में मांग और आपूर्ति का संतुलन न होना तथा देश में बढ़ती खुदरा महंगाई, मांग के अनुरूप खाद्य पदार्थ का सीमित उत्पादन उत्पादनङ्क विक्रेता को अधिक मुनाफा कमाने की लालसा, खाद्य पदार्थ के बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए विक्रेता सस्ते दामों पर खाद्य पदार्थों को बेचते हैं, जो पूरी तरह मिलावटी होता है। देश में बाजार का आकर जैसेझजैसे बढ़ता गया वैसेझवैसे मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार भी बढ़ता गया। बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों में कुछ न कुछ मिलावट जरूर होती है। बाजार में उपलब्ध कुल खाद्य पदार्थों में 35-40 प्रतिशत मिलावटी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा हमेशा से होता रहा है लेकिन त्योहारों के दिनों में यह गोरखधंधा तेजी से बढ़ता है। खाद्य पदार्थों में बहुत खतरनाक रसायनों का उपयोग किया जाता है। चीनी में चॉक पाउडर, सरसों के तेल में आर्जीमोन के बीज, मसालों में रासायनिक रंगों, दूध में डिटर्जेंट स्टार्च, पनीर को बनाने के लिए यूरिया, कोलतार डाई, पाम ऑयल जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के सुरक्षा मानकों की सही देखरेख न होने से मिलावट के धंधे को बढ़ावा मिलता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अनुसार देश में कुल बेचे जाने वाले दूध और दूधयुक्त पदार्थों में 68.7 प्रतिशत मिलावट होती है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से फूड प्वॉइजनिंग, एलर्जी, इम्यून सिस्टम का कमजोर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मिलावटी खाद्य पदार्थों को रोका नहीं गया तो 2025 के अंत तक 87 प्रतिशत लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में पिछलचार वर्षों में मिलावटी खाद्य पदार्थों के आपराधिक मामलों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 2020-21 में 3869 जबकि 2023-24 के बीच में 4737 मामले दर्ज किए गए।

दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में उत्तर भारत में मिलावट की समस्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में मिलावट का धंधा बड़े पैमाने पर फैला हुआ है।

सवाल उठता है कि मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सरकार पूरी तरह प्रतिबंध लगाने में नाकाम क्यों रहती है? बड़े त्योहारों पर ही क्यों खाद्य सुरक्षा विभाग अपनी सक्रियता दिखाता है? मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा साप्ताहिक जागरूकता अभियान तथा मिलावट की आशंका वाले खाद्य उत्पादों की समयझसमय पर निगरानी करते रहना चाहिए। मिलावट खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देश भर में बढ़ती खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। इसलिए उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्कता बरतनी चाहिए तथा पैकेटबंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय एक्सपायरी डेट अवश्य देखनी चाहिए। मिलावटी खाद्य पदार्थों के चक्कर में उपभोक्ता का नुकसान होता है, और उसे गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ से वंचित होना पड़ता है।

नदियों का प्रदूषण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी

नदियों में सीवरों और गंदे नालों का पानी बिना शोधित किए न जाने पाए, यह देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और उनके नगर निकायों की है, लेकिन वे इसमें कोताही बरत रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अभी भी नदियों का प्रदूषण जारी है। इसका कारण यह है कि जहां सीवेज शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, वहीं अनेक शहरों के गंदे नाले अभी तक इन संयंत्रों से नहीं जोड़े जा सके हैं।

दुनिया के अन्य देशों की तरह अपने देश में भी तमाम शहर नदियों किनारे बसे हुए हैं। समय के साथ नदियों के तट पर आबादी का घनत्व भी बढ़ रहा है। इस आबादी के एक बड़े हिस्से के पास सीवेज सिस्टम नहीं है, क्योंकि वह अनधिकृत कॉलोनियों में अधिक रहती है। इसके अलावा शहरों का जो सीवेज सिस्टम है, वह पुराना पड़ चुका है। समस्या इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि सीवेज सिस्टम पर्याप्त क्षमता के नहीं हैं। वे सीवरों का पूरा गंदा पानी शोधित नहीं कर पाते। इस–के चलते सीवरों का गैर शोधित पानी सीधे नदियों में जाता है। यह स्थिति महानगरों में भी है। पिछले दिनों दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद से यमुना की सफाई पर खूब चर्चा हो रही है। चुनाव में यमुना का प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार भी यमुना को साफ करने की बात करती थी, लेकिन वह नाकाम रही। इसका एक कारण राज्य और केंद्र सरकार का झगड़ा भी रहा। इस झगड़े की वजह से यमुना की सफाई प्राथमिकता नहीं बन सकी।

जलशक्ति मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई यह जानकारी निराश करने वाली है कि नदियों के प्रदूषण को दूर करने का काम सही तरह नहीं हो पा रहा है। यह स्वीकारोक्ति इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि एक लंबे समय से कहा जा रहा है कि नदियों में सीवरों का गैर शोधित पानी नहीं गिरने दिया जाएगा। बीते दिनों संसद में दी गई जानकारी से यह पता चल रहा है कि सीवेज सिस्टम की खामी से नदियों को प्रदूषण मुक्त करने में बाधा आ रही है। 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही जब गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान नए सिरे से शुरू किया और इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई, तब यह उम्मीद बंधी थी कि इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के साथ अन्य नदियों को प्रदूषित होने से रोकने में सफलता मिलेगी, लेकिन स्थिति यह है कि अभी गंगा को भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सका है।

शायद ही कोई दल हो, जो नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की बात न करता हो, लेकिन इसके बाद भी वे प्रदूषित बनी हुई हैं। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। नदियों के प्रदूषित होने का एक बड़ा कारण नगर नियोजन से संबंधित नौकरशाही का नकारापन भी है। नौकरशाही ने नदियों किनारे होने वाली अनियोजित बसाहट को रोकने में उदासीनता का ही परिचय दिया है। उन्होंने इसे लेकर सरकारों को आगाह भी नहीं किया।

नदियों के प्रदूषण में नौकरशाही की भूमिका पर कभी कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। अच्छा हो कि सरकार

आज उन अनेक शहरों की सीवेज व्यवस्था सही तरह काम कर रही है, जिनका निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन हमारे इंजीनियर हर किस्म के आधारभूत ढांचे का निर्माण इस तरह करते हैं कि वह दो-चार साल में ही कमजोर पड़ जाता है या अपर्याप्त साबित हो जाता है।

इस पर कोई श्वेतपत्र लाए कि नदियां क्यों प्रदूषित हैं? श्वेतपत्र में इसका भी उल्लेख किया जाए कि जब नदियों किनारे बसाहट हो रही थी, तब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बढ़ती आबादी के लिए उपयुक्त सीवेज सिस्टम का निर्माण क्यों नहीं करा रहे थे?

यदि यह मान लिया जाए कि पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आखिर इसका क्या मतलब कि अब भी ध्यान न दिया जाए। एक ऐसे समय जब केंद्र के साथ राज्य सरकारों की ओर से नदियों को साफ करने के दावे किए जा रहे हैं, तब सीवेज सिस्टम में सुधार न हो पाना, गंदे नालों का सीवेज शोधन संयंत्रों से न जुड़ पाना और इन संयंत्रों का पूरी क्षमता से काम न कर पाना चकित करता है। अरबों रुपए सीवेज व्यवस्था को दुरुस्त करने में खर्च किए जा चुके हैं, पर यही तथ्य बार-बार सामने आता है कि यह व्यवस्था अपर्याप्त और असंतोषजनक है। सीवेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बनाए गए कई सीवेज शोधन संयंत्र एक-दो साल चलने के बाद ही बंद हो जाते हैं।

आज उन अनेक शहरों की सीवेज व्यवस्था सही तरह काम कर रही है, जिनका निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन हमारे इंजीनियर हर किस्म के आधारभूत ढांचे का निर्माण इस तरह करते हैं कि वह दो-चार साल में ही कमजोर पड़ जाता है या अपर्याप्त साबित हो जाता है।

नदियों में प्रदूषण केवल सीवेज सिस्टम की खराबी से ही नहीं होता, बल्कि उद्योगों के अपशिष्ट जल से भी होता है। गंभीर बात यह है कि तमाम उद्योग अपने विषाक्त जल को शोधित करने के बजाय उसे रिवर्स बोरिंग कर जमीन में समाहित कर देते हैं। यह अपराध है, लेकिन उस पर रोक इसलिए नहीं लग रही है, क्यों-कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारी ऐसे उद्योगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते। इसका नतीजा यह है कि उद्योग जानबूझकर भूजल को दूषित कर रहे हैं। यह दूषित जल भूगर्भ जल को विषैला करता है और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। पंजाब में कैंसर के मामले बढ़ने के पीछे भूमिगत जल के प्रदूषण को ही माना जा रहा है। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने वाली व्यवस्था तब सुधरेगी, जब शासन-प्रशासन के साथ आम जनमानस भी सचेत होगा।

सरकारी कर्मचारी और विशेष रूप से इंजीनियरों पर यह दारोमदार होता है कि वे बेहतर इंजीनियरिंग और गुणवत्ता वाले निर्माण कराएं, लेकिन इसमें शिथिलता ही देखने को मिलती है। यह किसी से छिपा भी नहीं, लेकिन इसके बाद भी इंजीनियरों को जवाबदेह बनाने और उन्हें उनके घटिया निर्माण के लिए दंडित करने का काम नहीं हो पा रहा है।

पिछले दिनों सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सड़कों के निर्माण और डिजाइनिंग में खामी इसलिए देखने को मिल रही है, क्योंकि इंजीनियर उनका निर्माण सही तरह नहीं करते। यह हाल एनएचएआइ के इंजीनियरों के साथ अन्य सरकारी विभागों का भी है। आज जब हम संकल्प ले रहे हैं कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है, तब यदि बेसिक इंजीनियरिंग में भी दक्षता हासिल नहीं की जा पा रही है तो यह शर्म की बात है।

घूँघट की बगावत

16 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

▸ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर नरसिंह महराज गी उतारी आरती और लोगों के साथ खेली होली

पूरे देश में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और जनता के साथ इस उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने होली के मौके पर राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब इसके लोग एकजुट रहेंगे।

आकर्षण का केंद्र बनी महिला स्टॉल्स

सुजानपुर(हमीरपुर)। ऐतिहासिक चौगान सुजानपुर में शुरू हुए राष्ट्र स्तरीय होली मेले में इस बार महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्वयं सहायता समूहों की ओर से मोटे अनाज के बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जिसकी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रदर्शनी में समूहों की ओर से अचार, चटनी, मुरब्बा के साथ सेहत के लिए लाभकारी मोटे अनाज से तैयार रागी के लड्डू, बाजरे की खिचड़ी, कोदरे की चाय, कोदरे के सिड्डू और नागा जौ के सिड्डू सहित अन्य उत्पाद बेचे जा रहे हैं। मेले में इस बार सबसे अधिक भीड़ महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों पर लग रही है। स्टॉल लगाने वाली महिला अनीता ठाकुर, नीलम, सुमन, कुसुम लता आदि ने कहा कि राष्ट्र स्तरीय मेले में महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए पहली बार कनोपी (टेंट) दी गई है। जिससे उत्पादों को बेचने में काफी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पाद आधुनिकता के इस दौर में धीरे-धीरे गांव से लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए उत्पादों को बेचने का कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को प्राचीन पद्धति के बारे में जागरूक किया जा सके। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को अपना हुनर दिखाने का जहां मौका मिल रहा है, वहीं उनकी आजीविका का भी एक साधन बन रहा है।

गोपीनाथ मंदिर में खेली गई भव्य होली

देहरादून। उत्तराखंड में जगह-जगह होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। सियासत पर होली का रंग चढ़ा। सीएम भी सबके संग खूब झूमे। सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्रियों हरीश रावत, भगत सिंह कोश्यारी और तीरथ सिंह रावत के आवास पर जाकर होली की शुभकामनाएं दीं और रंग लगाया। वहीं गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में भव्य होली खेली गई। ओटूवा बेलेणा, लगैलो मडांण,बेडु पाको, ओ लाली, रंगिली बिंदुली घाघर काई, मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़ी समेत अन्य कई पहाड़ी गानों पर लोग थिरकते नजर आए। इस दौरान पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप पर पूरे उत्साह के साथ छोलिया, झोड़ा आदि लोकनृत्य भी करते दिखाई दिए।

वहीं गोपीनाथ मंदिर में खेली गई होली बेहद खास रही। होली पर्व यूं तो देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन चमोली जनपद के गोपेश्वर में होली पर्व अनूठे ढंग से मनाया जाता है। यहां गांव-गांव से पहुंची होल्यारों की टोली भगवान गोपीनाथ के मंदिर में होली मनाने पहुंचते हैं। इस दौरान मंदिर की रंगत देखते ही बनती है। दिनभर भोलेनाथ संग होली खेलने के बाद टोलियां अपने-अपने क्षेत्र के लिए लौट जाती हैं। लंबे समय से यहां यह परंपरा चल रही है। स्थानीय मान्यता है कि गोपीनाथ मंदिर क्षेत्र में ही श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष होली पर्व अनूठे ढंग से मनाया जाता है। नगर क्षेत्र के साथ ही समीपवर्ती गांवों से होल्यारों की टोली मंदिर में पहुंची। यहां भगवान गोपीनाथ को अबीर, गुलाल अर्पित करने के बाद सभी टोलियां मंदिर परिसर में एकत्रित हुई, जिसके बाद यहां लाउडस्पीकर और पारंपरिक वाद्ययंत्र ढोल-दमाऊं की थाप पर होल्यार झूमकर नाचे। यहां की होली भोलेनाथ को समर्पित होती है। कहा कि जिस तरह ब्रज में कान्हा के साथ होली मनाई जाती है, उसी तरह गोपेश्वर में होल्यार गोपीनाथ भगवान के संग होली खेलते हैं। यह क्षण दिव्य और भव्य होते हैं।

विलुप्त प्रजाति के गिद्ध को बकाणी में किया रेस्क्यू

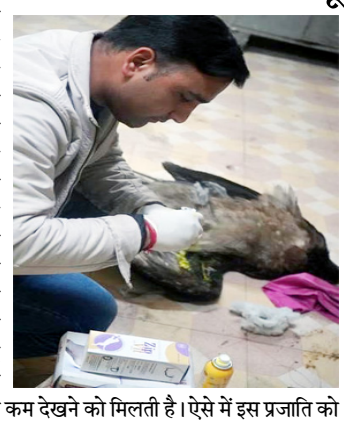

चंबा। वन विभाग की टीम ने बुधवार को विलुप्त प्रजाति के गिद्ध को रेस्क्यू किया। चंबा-भरमौर एनएच पर बकाणी के पास एक गिद्ध सड़क किनारे जख्मी हालत में पड़ा था। उसे कुत्ते अपना शिकार बनाने की फिराक में थे। इसकी सूचना जैसे ही वन विभाग को मिली तो वन रक्षक विनोद कुमार अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। जख्मी गिद्ध को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया। इसके बाद उसे उपचार के लिए वन विभाग के ट्रीटमेंट केंद्र पहुंचाया गया। यहां पता चला कि पतंग की डोर में फंसने से इस गिद्ध का पंख जख्मी हो गया था। जख्म गहरा हो चुका था। इसकी वजह से वह उड़ने में असमर्थ हो था। जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक उसे वन विभाग के ट्रीटमेंट केंद्र में ही रखा जाएगा। वन मंडल अधिकारी चंबा कृतज्ञ कुमार ने बताया कि विलुप्त प्रजाति का एक गिद्ध बकाणी में घायल अवस्था में मिला है। उसके इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। यह प्रजाति आज के परिवेश में बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे में इस प्रजाति को बचाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

सनातन धर्म जितनी समृद्ध पर्व-त्योहारों की परंपरा दुनिया के किसी भी मजहब के पास नहीं : योगी

गोरखपुर(जीकेबी)। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म जितनी समृद्ध पर्व-त्योहारों की परंपरा दुनिया के किसी भी अन्य देश में या मत, मजहब के पास नहीं है। हमारी आस्था ही सनातन धर्म की ताकत है और आस्था की आत्मा पर्व त्योहार में है। सनातन पर्व परंपरा में दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक वर्षभर उत्साह और उमंग से जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है।

सीएम योगी गत दिनों शुक्रवार को होली के पावन महापर्व पर घंटाघर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व श्री होलिकोत्सव समिति की ओर से निकलने वाली भगवान नृसिंह की रंगभरी शोभायात्रा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। सभी प्रदेशवासियों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पौराणिक गाथा गाथा के अनुसार भारत में जन्म लेना दुर्लभ है। और उसमें भी मनुष्य रूप में, सनातन धर्म में जन्म लेना और भी दुर्लभ। जो लोग सनातन को कोसते थे उन्होंने भी सनातन का सामर्थ्य प्रयागराज महाकुंभ में देखा है। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पावन त्रिवेणी में न कर पुण्य के भागीदार बने। दुनिया में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा को बोलने वाला सनातनी रहा हो, उसने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर जीवन को धन्य बनाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ को दुनिया विस्मयकारी भाव से, कौतूहल भरी निगाहों के साथ देख रही थी। जबकि सनातन धर्म के लोग इस महाकुंभ के माध्यम से पूरे विभ को एकता का संदेश देने के लिए जुड़के हुए थे। प्रयागराज में अद्भुत मर्यादा और अद्भुत अनुशासन देखने को मिला। वहां ऐसी एक भी घटना नहीं हुई जिसके कारण सनातनी लोगों को सिर नीचे करना पड़ता।

सीएम योगी ने कहा कि जाति और अस्पृश्यता के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को प्रयागराज महाकुंभ को जरूर देखना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो या सामान्य नागरिक बड़े से बड़ा धर्माचार्य हो या गांव का योगी सबने एक घाट पर एक भाव से आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करने वाले और समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। जिन्होंने गो तस्करी में लिप्त लोगों को संरक्षण दिया। जिन्होंने यह मान रखा था कि भारत कभी विकसित नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों की मंशा देश और सनातन ार्म के प्रति जगजाहिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है। यतो धर्मस्ततः जयः। जहां धर्म है वही विजय होगी। विजय पथ के लिए कठिन साधना और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। साधना जितनी कठिन होगी, सिद्धि उतनी बड़ी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वह तभी पूर्ण होगा जब भारत एक होगा और जब भारत एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, तब उसे विकसित होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी साधना राष्ट्रमाता के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों के के प्रति अपनी मंगलकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि होली का एक ही संदेश एकता से ही आगे रहेगा यह देश। उन्होंने कहा कि अगर देश अखंड रहेगा तो एक भारत-श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना अवश्य पूरी होगी। उन्होंने भगवान नृसिंह के अवतार का उल्लेख करते हुए कहा कि यह चेतावनी भी है कि हिरण्यकश्यप जैसे लोगों का घमंड नहीं टिक सकता और एक उदाहरण भी है कि यदि भक्त प्रहलाद के अनुरूप सत्य के मार्ग का अनुसरण किया जाएगा तो ईश्वर की कृपा जरूर बरसेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कहा कि ऐतिहासिक महाकुंभ के आयोजन के बाद यह होली अत्यंत विशेष है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में दुनिया ने सनातन धर्म का दर्शन किया और सनातन ार्म की सद्भावना देखी।

प्रगति के नए अध्याय गढ़ता बीमारू राज्य बिहार

विकास को लेकर न सिर्फ राज्यों का नया-चरित्र उजागर हुआ है बल्कि गहराई से देखने में आया है कि राज्य सरकारें अपने राजनीतिक स्थायित्व के लिए विकासवादी लीक पर आगे बढ़ने को विवश हैं। राज्यों का यह विकासवादी चरित्र उस दौर में उभरा है, जब बीमार ठहराए गए राज्य विकास के विभिन्न मोर्चों पर अपने मॉडल के साथ-चर्चा में हैं। हाल में बिहार में नीतीश सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया। गौरतलब है कि इसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए सात बड़ी घोषणाएं की हैं जिनमें कन्या विवाह, मंडप निर्माण, महिला हाट, जिम ऑन व्हील, पिंक टॉयलेट, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, पिंक बस और महिलाओं को ट्रेनिंग देना शामिल है। ऐसी पहल का महत्व तब ज्यादा समझ में आता है जब हम जेंडर या पिंक बजट की बात करते हैं। बिहार सरकार के तकरीबन तीन लाख 17 हजार करोड़ के बजट को पिंक बजट के फ्रेम में देखें तो यह राज्य में महिलाओं की जिंदगी में बड़े बदलाव को रेखांकित करता है। यह बजट महिला स्वावलंबन की चिंता भी करता है। मसलन, इसमें उनके लिए कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम और आर्थिक मदद का प्रबंध किया गया है। अगर यह बात कही जा रही है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के चालक, परिचालक और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो यह महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बड़ा फैसला है। स्मरणीय है कि इस वर्ष देश में विधानसभा चुनाव होने हैं। पर इस चुनाव को दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधान सभा चुनाव की सोधी में देखें तो राज्यों के बदले अर्थ-चरित्र को समझ सकेंगे। मजेदार यह कि- राजनीतिक तौर पर भी यह सोच लाडली योजना से लाडला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। जो एक बड़ा बदलाव है। जाति और अस्मिता की राजनीति का उत्तर संग विकासवादी तर्कों पर कसा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि- यह समझ समाज और

बिहार आज देश में राज्यों के बदले अर्थ चरित्र का अग्रणी राज्य है जो सामाजिक सहभाग के साथ विकास की राह पर बढ़ रहा है बेहतर होगा कि ऐसे बदलाव की चर्चा में तात्कालिक राजनीतिक समझ दर किनार कर हम देख पाएंगे कि आशीष बोस की रिपोर्ट के उलट वर्तमान में कही ज्यादा प्रगतिशील आर्थिक व्याख्याकारो आवश्यकता है जो विकास के नए मानदण्डों के साथ उसके मील संदर्भों की चर्चा को आगे बढ़ाए।

सरकारों के स्तर पर एक साथ दिखाई पड़ रही है।

पुनः स्मरणीय है कि- विसर उन राज्यों में शामिल है जिसके विकास की संभावनाओं पर लंबे समय तक नकारात्मक विचार किया गया। इस पूरे संदर्भ का आगाज 1980 के दशक में तब हुआ जब जन सांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विश्लेषक आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट-चार बड़े राज्यों बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बताया । इन राज्यों को आर्थिक विकास स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सूचकांकों के मायने में पिछड़ने के कारण यह नाम दिया गया। इसके बाद न सिर्फ यह शब्द प्रचलन में आया बल्कि इस आधार पर इन राज्यों के विकास को अलग से चिन्हित और वगीकृत किया जाता रहा। पर बीते दशकों में यह स्थिति लगातार बदली है। जो लोग बिहार के जिलों, यहां के विषय भूगोल और परिवहन सेवाओं को लेकर जमीनी समझ रखते हैं वे समझ पाएंगे कि इससे महज प्रदेश की महिलाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा बल्कि लैंगिक समानता का एक नया दौर भी शुरू होगा। पंचायत में महिलाओं को 50 फीसदी सबसे पहले देने वाले राज्य में यह पहल उस सिलसिले की नई पहल है जिसमें बालिका शिक्षा और जीविका योजना जैसी पहल पहले से बदलाव के नए सुलेख साबित हो रही है। इसकी सबसे अच्छी बानगी है कि यह राज्य आज देश में पुलिस सेवा में शीर्ष महिला सहभाग वाला सूबा है। बात विकास और-चुनाव को लेकर एक साथ करें तो इस लिहाज से कई चीजे देखने और समझने की हैं। इस नई चर्चा और समझ के केंद्र में है नीतीश कुमार प्रगति यात्रा। खास तौर पर पारंपरिक ढर्रे दार चुनावी विमर्श में यह यात्रा बड़ा मोड़ और मास्टर स्ट्रोक है। बिहार के अनुभवी मुख्यमंत्री को इस बात की दाद तो मिलनी ही चाहिए कि ये सब वे बिना किसी सियासी हड़कंप और शोर-शराबे के कर रहे हैं। यह जरूर है कि अब जब उनकी प्रगति यात्रा पूरी हो चुकी है। तो उनके इस कदम को लेकर राजनीतिक गुणा- गणित का दौर तेज हो रहा है। राजनीतिक पंडित भी अब कहने लगे हैं कि-विकास के जिलावार खाके के साथ नीतीश ने नई जमीन तैयार कर दी है।

देश के राजनीतिक दिग्गजों की जमात में नीतीश ऐसे जाहिर राजनेता हैं जो रोड शो वाली राजनीति के दौर में भी सीधे जनता के बीच पहुंचने की राह पर है। 2005 से अब तक उन्होंने 15 यात्राएं की है।

2005 की न्याय यात्रा से लेकर मौजूदा प्रगति यात्रा तक उन्होंने बिहार की राजनीति और उसके प्रगतिशील लक्ष्यों को नये पर्याय दिए हैं, नए मानक दिए हैं। विकास को लेकर प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता का ही हासिल है कि-बीमारू राज्य की श्रेणी में आने वाला राज्य बिहार आज रोड कनेक्टिविटी से लेकर महिला सशक्तिकरण का सर्वथा भया आख्यान रच रहा है।

धूमधाम से मनी ग्रामीण क्षेत्रों में होली, लगाए एक दूसरे के अबीर-गुलाल, मिले गले

बड़हलगंज। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होली का त्योहार बड़हलगंज क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार को सुबह से ही युवको की टोलियां अबीर-गुलाल व रंगो के साथ सडक्क पर निकल पड़ी। एक बजे दिन में पं दीनदयाल चौक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में नृसिंहझ भगवान की झांकी के साथ होली का जुलूस निकला। जुलूस लेटाघाट, डीह स्थान, सोती चौराहा होते हुए बाबा जलेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण में पहुचा। जुलूस में कपड़ा फाड़ युवाओं की टोली फाग गीत पर थिरकते हुए जै श्रीराम जै श्रीराम का नारा लगाते हुए चल रही थी। सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाल चंद्रभान सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। इस दौरान कस्बे के विभिन्न मंदिरों में लोगो ने भगवान को अबीरझ्गुलाल चढ़ाया। खजनी थाना क्षेत्र के उनवल चौकी अंर्तगत उनवल सहित आस पास के गांवों में रंगों का पावन पर्व होली इस बार भी बड़े ही धूम-धाम से शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया अबतक की जानकारी के हिसाब से कही भी कोई अप्रिय घटना सुनने को नही मिली उम्र दराज लोग जहा अबीर गुलाल के साथ होली खेली वही बच्चों ने जमकर गाजे बाजे के साथ रंगों सहित अन्य सभी तरीको से होली मनाई।

बाबा झारखण्डी महादेव के स्थान पर टोलियों में लोग गाजे बाजे के साथ फगुआ गीत गाते होली मनाई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनवल नगर पंचायत अध्यक्ष महेश कुमार दुबे ने होली पर्व के अवसर पर अपने आवास पर अपने शुभचिंतको व सभासद गण एवं कार्यकताओं के साथ अबीर गुलाल लगाकर होली खेली तथा वहा उपस्थित लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान सभी लोगों ने भी नगर अध्यक्ष महेश कुमार दुबे को अबीरझ्गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी सभासद गण एवं कार्यकताओं को मिष्ठान्न खिलाकर होली पर्व का आंनद लिया गया। इस पर्व पर लोगो ने एक दूसरे से गले लगकर अपने सभी गिले शिकवे को मिटा बहुत ही शांति पूर्ण ढंग से नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल में होली मनाई गई। इसी क्रम में कैंपियरगंज स्थानीय थाना क्षेत्र में रंगो का महापर्व होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पंचायत कस्बा सहित गांवों में फगुआ गीत गाया गया। लोग एक दूसरे को रंग अबीर से सराबोर करते रहे। लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। क्षेत्र में पुलिस व तहसील प्रशासन ने सुरक्षा के कडक्ष प्रबंध किए थे। नगर पंचायत में चेयरमैन प्रतिनिधि गोपाल सिंह व ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक प्रमुख अिभनी जायसवाल लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील करते दिखे। होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। होलिका दहन स्थलों पर पुलिस बल तैनात रही। थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह के नेतृत्व में पुलिस पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रही।

आयोग की मतदाता सूची फुल प्रूफ नहीं

लोकतंत्र में निर्वाचन प्रणाली बहुत मायने रखती है कि-स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी -चुनाव हो जिससे लोगों को लोकतंत्र में भरोसा बना रहे। लेकिन जिस प्रकार की विसंगतियां प्रथम दृष्टया प्रकाश में आ रही हैं उससे यही लगता है कि- निर्वाचन आयोग को मतदान सूची फुल प्रूफ नहीं है। देश में 1952 से लगातार चुनाव हो रहे हैं जिसमें लोक सभा विधानसभा के चुनाव होते हैं। प्रत्येक चुनाव में मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम न होने, गलत

नाम होने गलत फोटो होने, मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को अपने नाम तलाशने में इधर-उधर भटकना अभी भी हो रहा है। आमतौर ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं दे पाये हैं कि कोई भी व्यक्ति इस पर अंगुली न उठा सकें। एक स्वस्थ लोकतंत्र एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि चुनाव की प्रक्रिया संदेह से परे होनी चाहिए।निर्वाचन आयोग द्वारा विपक्षी दलों द्वारा अलग-अलग राज्यों के मतदाताओं के एक ही ईपीआईसी यानी मतदाता पहचान पत्र संख्या एक होने के मुद्दे को उठाने के बाद कहा गया है कि एक ही मतदाता पहचान पत्र होने का फर्जी अदला बदली नहीं है। निर्वाचन आयोग इसके लिए अपनी दलील देता है कि- मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र एक समान संख्या के हो सकते हैं। लेकिन इसमें दर्ज जनसांख्यिकी विवरण विधान सभा क्षेत्र और मतदान केन्द्र जैसे विवरण अलग-अलग हैं। संबंधित मतदाता

अपने ही मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकता है। जहां उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। वह कहीं और वोट नहीं डाल सकता है। इसलिए यह आरोप लगाना कि मतदाता सूची में हेरा फेरी की गई है निराधार है। आयोग का अपनी सफाई में कहना कि यह पहले अपनाई गई विकेंद्रीकृत और मैन्युअल प्रणाली के कारण हुआ जिसकी वजह से कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों ने एक ही ईपीआईसी अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला का उपयोग किया इसके कारण विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में मतदाताओं को डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर आवंटित हो गए। लोकसभा चुनाव के परिणामोंपरान्त उत्साहित विपक्षी दलों को जब-हरियाणा, दिल्ली, और महाराष्ट्र के चुनावों में करारी हार मिली तो मतदाता सूची से लेकर उन सभी कारणों के विश्लेषण में इन दलों को आरोप है कि किस प्रकार से मतदाता सूची को खास तौर पर

अपने अनुरूप सत्तारूढ़ दल ने उपयोग किया है। और राज्यों से लोगों को बुलाकर फर्जी मतदान कराया गया है। विपक्षी दलों द्वारा यह विसंगति

को दूर किया जा सके। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य कई विपक्षी दलों का आरोप था कि भाजपा की चुनाव मशीनरी तीन चार तरीकों से चुनाव जीतने का कार्य कर रही है जिसमें फर्जी मतदाताओं की लम्बी सुची है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को चुनाव में मतदान करने के लिए ले जाये जाते हैं। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम जुड़वाए जाते हैं और अन्य दलों के मतदाताओं के नाम कटवाये जाते हैं तथा उनके मतदाता सूची में से मतदान केन्द्र को एक जगह से दूसरे जगह कर दिया जाता है जिसकी वजह से लोग अपना नाम नहीं पाकर बिना वोट दिए ही लौट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग पांच बजे के बाद का जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है वह सन्देहों को जन्म देता है। विभिन्न राजनीतिक दल यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत जारी कर सकता है तो कितने लोगों ने मतदान किया यह क्यों नहीं बता पाता है। जबतक प्रत्येक मशीन पर इसका उल्लेख किया जाता है। इन सब स्थितियों से यही लगता है कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था में ही इतनी विसंगतियां है जिसका शिकार मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र हो रहा है। अभी तक जो राजनीतिक दल हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के नतीजों के बाद अब वे नये निष्कर्षों पर पहंच रहे हैं।

संप्रदायवादी सोच से ऊपर उठे सरकार

भारत सरकार ने गोपाल सिंह समिति रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर समिति नियुक्त कर मुसलगानों की माली हालत का जायजा लेने का प्रयास किया। इन सभी समितियों और आयोगों की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और पिछले कुछ दशकों में उसमें गिरावट आई है। सच्चर कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि - इस असहाय समुदाय की मदद के लिए सरकार कदम उठाएगी। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए घटक योजना को फिर से और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक विकास के फल का स्वाद अन्य समुदायों की तरह चख सकें, हमें नवोन्मेषी योजनाएं बनानी होगी। संसाधनों पर उनका सबसे पहला दावा होना चाहिए। केंद्र की कई जिम्मेदारियां भी है। जिन्हें संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप पूरा किया जाएगा।

भाजपा ने मुसलमानों की मदद करने की बात को हिन्दुओं को लूटने से जोड दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि - वे अब पता लगाएंगे कि हमारी माताओं-बहनों के पास जितना सोना है वे उसे तोलेंगे, उसकी कीमत का अंदाजा लगाएंगे और फिर वो उसे बांट देंगे और वे उसे किन लोगों को देंगे यह डाक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है।

इस पृष्ठभूमि में यूएस-इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस की हालिया रिपोर्ट स्वागत योग्य है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है: रि थिंकिंग एक्शन फॉर मुस्लिम इन कंटेंपरेरी इंडिया और इसे हिलाल अहमद, मोहम्मद संजीर आलम एवं नजीमा परवीन ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे से हटकर बात करती है। रिपोर्ट यह स्वीकार किया गया है कि- मुसलमानों में अलग-अलग आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं। कुछ लोग धनी है। और उन्हें आरक्षण की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अन्यों के मामले में रिपोर्ट उनके धर्म के बजाय उनकी जाति पर ध्यान देने की बात कहती है। रिपोर्ट यह बताती है कि यह देखा जाना चाहिए कि वे लोग पारंपरिक रूप से कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है।

हमारी सत्ता धारी पार्टी अल्पसंख्यकों को करीब-करीब दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। मगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या वर्तमान सरकार अपनी संकीर्ण संप्रदायवादी सोच से ऊपर उठकर रात को लागू करेगी?

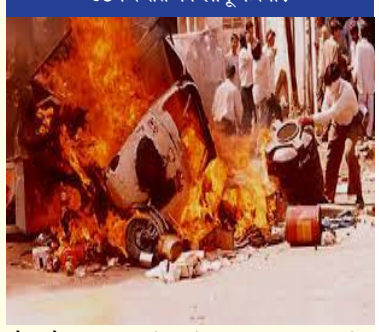

रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण पर लगाई गई 50 प्रतिशत की उच्च सीमा को हटाए जाने की मांग की जा रही है। इसके बाद मुसलमानों को ओबीसी और दलित कोटे की जगह दी जा सकती है। रिपोर्ट में सीएस डी एस-लोकनीति द्वारा संकलित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट लेखक के अनुसार, मुसलमानो के लिए आरक्षण की बात करना सांड को लाल कपडा दिखाना जैसा है। इसलिए उन्हें उनके धर्म की बजाए उनके पेशे के आधार पर ओबीसी या एससी कोटे में जगह दी जानी चाहिए। पसमांदा मुसलमान सबसे पिछड़े हैं और उन्हें दलितों की श्रेणी में रखा जा सकता है। कई ईसाई समुदायों की भी स्थिति ऐसी है। उन्हें भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सरकार की मदद की जरूरत है।

जो लोग न्याय और बराबरी के आदर्शों में यकीन रखते हैं उनके लिए अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की माली हालत गंभीर चिंता का विषय है। भारत में इस्लाम 7वीं सदी में अरब व्यापारियों के साथ मालाबार तट के रास्ते आया। तब से बड़ी संख्या में हिंदुओं ने इस्लाम अपनाया है। मगर इनमें ज्यादातर लोग वे थे जो हिंदू धर्म में जातिगत दमन के शिकार थे और आर्थिक रूप से वंचित थे जिसे हम मुगल काल कहते हैं उसमें मुस्लिम बादशाह दिल्ली और आगरा से राज भले ही करते थे पर उनके राज से सामाजिक क्षेत्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकांश जमींदार हिंदू थे और वे व्यवहार करने के मामले में गरीब मुसलमानों और गरीब हिंदुओं के बीच कोई भेदभाव नहीं करते थे।

सन 1857 के विद्रोह के बाद मुसलमान अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। कारण-इस विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर थे। मुस्लिम समुदाय को अंग्रेजों के गुस्से का सामना करना पड़ा। स्वाधीनता के बाद मुसलमानों के बारे में मिथक और उनके प्रति पूर्वाग्रह मजबूत होते गए और वे साम्प्रदायिक ताकतों के सबसे बड़े शिकार बन गए। जहां अन्य समुदाय आगे बढ़े और उनके सदस्यों में शिक्षा और रोजगार हासिल किए वहीं कई कारणों से मुसलमान पीछे छूट गए। इन कारणों में उनके खिलाफ दुष्प्रचार और उनकी आर्थिक बदहाली शामिल थी।

हमारे संविधान ने यह स्वीकार किया है कि दलित और आदिवासी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं और उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस आरक्षण से इन समुदायों को कुछ हद तक लाभान्वित किया जा सका। ओबीसी का प्रश्न है उन्हें 1990 से राष्ट्रीय स्तर पर 27 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हुआ। लेकिन कई राज्यों में इसके पहले से ही अपने स्तर पर उन्हें आरक्षण देना शुरू कर दिया था। ओबीसी को आरक्षण का मुख्य और इक्वालिटी जैसे संगठनों ने कड़ा विरोध किया था।

दलितों के लिए आरक्षण का भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। सन 1980 में और फिर 1985 में गुजरात में दलित विरोधी हिंसा हुई। इस कारण अल्पसंख्यक आर्थिक बदहाली के दलदल में धंसते गए इसका कारण यह था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। कुछ राज्यों ने ओबीसी कोटे के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया। अगर इसका विरोध हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों ने जमकर विरोध किया। मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति के खराब होने के कई कारण है। उनके खिलाफ हिंसा होती रही और हिंसा के डर से वे अपने मोहल्लों में सिमट गये हैं। वे ऐसे इलाकों में रहना पसंद करने लगे है जहां उनके आस-पास मुसलमान ही रहते हो उन्हें नौकरियां मुश्किल से मिलती है और उनमें शिक्षा का स्तर भी कम है इस सबके बद जब भी मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात होती है तो हिन्दुत्व की राजनीति के पैरोकार जोर-जोर से बोलने लगते हैं। वे इसे मुसलमानों का तुष्टिकरण बताते हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है धीरे-धीरे अपने भारतीय राज्य एक खैराती संस्था बन गया है। जो सरकार की योजनाओं की जद में आने वालों को लाभार्थी कहता है। रिपोर्ट के लेखक कहते हैं कि ओबीसी को तार्किक और धर्म से ऊपर उठकर उपवर्गीय किया जाना चाहिए। वर्तमान में चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किया जाना जरूरी है। हमें सकारात्मक कदम उठाने होंगे। अगर किन्ही दो उम्मीदवारों की अर्हताएं और अनुभव समान हैं तो उनमें से जो जाति या विंग के कारण हाशियाकृत हो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुस्लिम समुदाय में बड़ी संख्या में शिल्पकार हैं। उन्हें बेहतरीन तकनीकी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह रिपोर्ट वर्तमान हालात को ध्यान में रखकर व्यापकत्व के रूप तैयार की गई है।

जीवंत होली उत्सव की साक्षी बड़वा की समृद्ध होली परम्परा

गांव के ऐतिहासिक झांग आश्रम में सबसे बड़ी डफ मंडली बसंत पंचमी पर एक उत्सव की शुरूआत करती है, जो गांव के हर कोने को जीवंत धमाल से भर देती है। इसी तरह, बाबा रामदेव मेला मंदिर में होली उत्सव एक अनूठी शैली में मनाया जाता है। होली के दौरान, मंदिर में एक भव्य डफ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से शीर्ष डफ और धमाल टीमें भाग लेती हैं। होली का यह उत्सव विशेष रूप से राजपूत समुदाय में खास होता है, जहां लोग भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हुए खुशी-खुशी रंग-बिरंगे गुलाल खेलते हैं। बड़वा में, राजपूत परिवार बसंत पंचमी से होली का जश्न शुरू करते हैं, और यह उत्साह गणगौर तक जारी रहता है।

होली भारत के सबसे प्रिय और भव्य त्योहारों में से एक है। दो दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के पहले दिन को 'छोटी होली' या होलिका दहन के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे दिन को 'रंगवाली होली' या फाग के नाम से जाना जाता है। पहले दिन की शाम को होलिका दहन होता है, जहाँ लोग अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं। दूसरे दिन भोर होते ही, रंग-बिरंगे रंगों और पानी के साथ उत्सव की शुरूआत होती है और सभी लोग खुशी-खुशी होली खेलते हैं। भारत में, लोगों को एक-दूसरे पर रंग छिड़कने के लिए दौड़ते हुए देखना आम बात है, और हरियाणा में देवर-भाभी द्वारा मनाई जाने वाली कोरडा मार होली इस मस्ती में एक अनोखा मोड़ लाती है। यह खूबसूरत त्योहार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है।

हरियाणा के सिवानी के बड़वा गाँव की होली काफी प्रसिद्ध है। यहाँ उत्सव डेढ़ महीने तक चलता है। दशकों से, राजपूत परिवार बड़वा में अपने जीवंत होली उत्सव के लिए जाने जाते हैं। भिवानी जिले का यह गांव अपने अनोखे तरीके से त्यौहार मनाने के लिए मशहूर है। बड़वा के युवा लेखक डॉ. सत्यवान सौरभ और प्रियंका सौरभ के अनुसार होली की परंपरा बसंत पंचमी से शुरू होती है और गणगौर पूजा तक जारी रहती है। बड़वा गांव को एक पवित्र स्थान माना जाता है, जिसकी संस्कृति समृद्ध है और जहां 36 समुदायों के लोग सद्भाव से रहते हुए त्योहारों के दौरान अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों को कायम रखते हैं।

बड़वा गांव में होली एक जीवंत उत्सव है जो विभिन्न प्रमुख स्थानों के साथ-साथ गांव के कोने-कोने में भी मनाया जाता है। उत्सव की शुरूआत प्राचीन झंग आश्रम से होती है, जहां सबसे बड़ी डफ मंडली बसंत पंचमी से अपना जीवंत धमाल नृत्य शुरू करती है। यह ऊजार्वान जुलूस आश्रम से अलग-अलग इलाकों में घूमते हुए पूरे गांव में फैलता है। होली का एक और आकर्षण बाबा रामदेव मेला मंदिर में मनाया जाने वाला उत्सव है, जहां एक भव्य डूफ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। विभिन्न उत्तर भारतीय राज्यों की टीमें अपनी बेहतरीन डूफ और धमाल प्रस्तुतियां देती हैं, रात भर नृत्य से मनोरंजन करती हैं, जिसमें विजेता टीम को नकद पुरस्कार मिलता है। पूरा गांव धमाल नृत्य का आनंद लेने के लिए मंदिर में इकट्ठा होता है।

राजपूतों के ऐतिहासिक गढ़ में भी होली मनाई जाती है, जहां त्योहार पर एकता और भाईचारे के प्रतीक गुलाल की रंगीन छटा बिखेरी जाती है। बड़वा में, राजपूत परिवार बसंत पंचमी से अपना होली उत्सव शुरू करते हैं, जिसमें कई लोग डफ बजाने में भाग लेते हैं। अन्य समुदायों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ उत्सव को और भी शानदार बनाते हैं। बड़वा एक बड़ा गांव है, और इसकी संकरी गलियां मुख्य चौराहों पर मिलती हैं। फाग के दौरान, ये चौराहे पारंपरिक कोरडा मार होली के साथ जीवंत हो उठते हैं, आज कोरड़ा प्रथा जो हरियाणा के कई हिस्सों में लुप्त होती जा रही है। हालाँकि, बड़वा में, इन चौराहों पर बड़े-बड़े पानी के टब लगाए जाते हैं, जो देवरों और भाभियों के समूहों से घिरे होते हैं, और जोशीले कोरडा मार होली और जीवंत संगीत से भरा एक आनंदमय माहौल बनाते हैं।

फाग से पहले के दिन, बड़वा गांव के निवासी श्रद्धापूर्वक होलिका स्थापित करने के लिए गुलिया और रोहसड़ा चौराहे पर एकत्र होते हैं। बाद में, ग्रामीण होली पूजा में भाग लेने के लिए एकत्र होते हैं। शाम होते ही, शुभ समय पर होलिका को आग लगाई जाती है, और सभी लोग उत्सव में शामिल होते हैं।बदलते दौर में, गाँव की सामाजिक संस्थाओं ने गुलाल तिलक और फूलों के साथ होली मनाने का एक नया रिवाज शुरू किया है, जो जल संरक्षण को बढ़ावा देता है और हानिकारक रंगों से दूर रहने का सन्देश देता है, साथ ही आधुनिक संवेदनाओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। जीवंत होली धमाल मुख्य रूप से गाँव के पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो हर गली में गूंजता है। दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े होकर डफ बजाते हैं, बीच में एक ढोलकिया और एक झांझ बजाने वाला होता है। सभी लोग एक घेरा बनाते हैं, एक साथ खुशी से गाते हैं। गाँव के पारंपरिक सपेरे उत्सव में शामिल होते हैं, घूमते हैं और बांसुरी बजाते हैं, प्रत्येक घर से छोटे-छोटे दान प्राप्त करते हैं। जैसे-जैसे वे एक घर से दूसरे घर जाते हैं, बांसुरी और अन्य वाद्ययंत्रों की ध्वनि हवा में गूंजती है और सभी प्रतिभागी उत्साह के साथ नृत्य करते हैं, एक-दूसरे को उत्साह बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

बड़वा गांव में होली वास्तव में एक उल्लेखनीय और शानदारउत्सव है। यह एक अनूठी परंपरा का प्रतीक है जो पूरे साल की थकान को दूर कर देती है। आज के समय में भी जब मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं, बड़वा में सामूहिक आनंद, कला और संस्कृति का मिश्रण हमेशा की तरह ही संजोया हुआ है। इस गांव की एक खासियत यह है कि यहां रंग, अबीर और गुलाल का इस्तेमाल सम्मानजनक और सभ्य तरीके से किया जाता है।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत और नेपाल का है आत्मीय संबंध : हृदय नारायण दीक्षित

लखनऊ । महिला दिवस पर रवीन्द्रालय चारबाग में चल रहे लखनऊ पुस्तक मेला में स्त्री विमर्श की गूंज रही तो साहित्यिक आयोजनों का दौर दिनभर चला। पहली मार्च से जारी इस मेले का कल रविवार को समापन हो जायेगा। मेले में आज उमड़े पुस्तक प्रेमियों के बीच नवयुग कन्या महाविद्यालय व अन्य कालेज के छात्र छात्राओं के हुजूम भी दिखायी पड़े।

किताबों और साहित्य सागर में यहां हर विषय की किताबें हैं। इन्हीं पुस्तकों में गुजरे दौर के लखनऊ के साथ आज का शहर भी है। अगर किसी को अवध की लखनउआ कहानियां, नवाबी के जलवे, अवध की बेगमें, नक्काल और भांड़, लखनऊ की शायरी फिल्म जगत में लखनऊ की योगदान, यहां के कथक घराने, संगीतकार, इमामबाड़े, यहां के गली मोहल्ले, काकोरी क्रान्ति जैसे राजधानी से जुड़े विषयों की प्रामाणिक जानकारी जानकारी चाहिए तो उसे मेले के स्टाल संख्या 53 पर पहुंचना होगा। यहां लखनऊ पुस्तकमाला की योगेश प्रवीन जैसे विशेषज्ञ लेखकों की सारगर्भित छोटी- छोटी पुस्तिकाएं हैं। इनमें 45वीं पुस्तिका ह्यषड़यंत्रों से घिरे लखनऊ के नवाबह्न हाल में शामिल हुई है।

मेले के साहित्यिक मंच पर आज कार्यक्रमों का समापन विमोचन भारत नेपाल मैत्री के क्रम में आयोजित कार्यक्रम से हुआ। मनीश शुक्ला के काव्य संग्रह निलम्बित मौन के स्वर का नेपाली भाषा में काठमाण्डू की मीना द्वारा किये अनुवाद ह्यप्रतिबंधित मौनह्न व एक अन्य किताब मै स्वयं सेवक का विमोचन पूर्व विधानसभाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल का युगों-युग से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आत्मीय संबंध

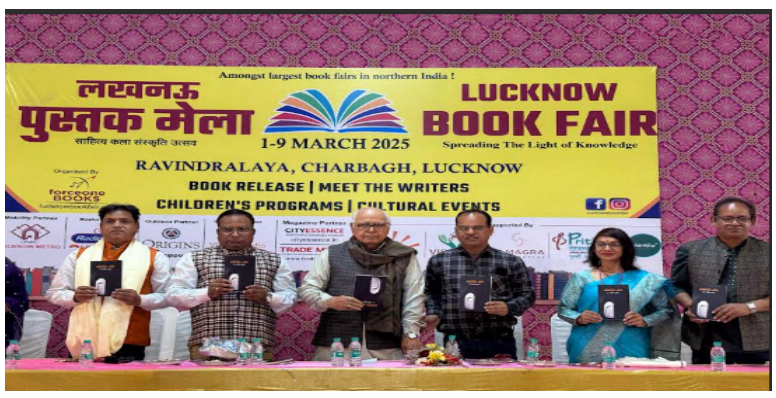

रहा है यह पुस्तक दोनों देशों के सांस्कृतिक सम्बन्धों की नई गाथा लिखती है इस अवसर पर भारत नेपाल साहित्य महोत्सव के अध्यक्ष डा.विजय पंडित, अनुवादिका मीना, रेणु मिश्रा ,श्रीधर अग्निहोत्री, लेखक मनीष शुक्ल व हरीश उपाध्याय उपस्थित थे।

सुबह नवसृजन संस्था की ओर से प्रो.उषा सिन्हा की अध्यक्षता में पुष्पा गुप्ता दोसर की काव्यकृति 'पुष्पांजलि' का विमोचन हुआ। समारोह में महेशचन्द्र द्विवेदी, डा.सुल्तान शाकिर हाशमी, आचार्य ओम नीरव, डा.योगेश, डा.शिवमंगल सिंह 'मंगल', मंजू सक्सेना, देवेश द्विवेदी 'देवेश' शामिल हुए।

इसी क्रम में शिक्षिका डा.रश्मि श्रीवास्तव की स्त्री विमर्श पर केन्द्रित किताबों ह्यरेशम के रिबनह्न और ह्यबैंकबेंचरह्न का विमोचन डा.सुधाकर अदीब और डा.अमिता दुबे ने किया। अलका प्रमोद द्वारा प्रेषित रेशम के रिबन पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत हुई तो डा.अमिता दुबे ने बैकबेंचर की समीक्षा करते हुए पुस्तक को विद्यार्थियों, शिक्षकों के लिये उपयोगी बताया। डा.सुधाकर अदीब ने पुस्तकों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। बैकबेंचर में विद्यार्थियों की मनःस्थिति सटीक चित्रण के साथ जीत जाने की होड़ से उपजती वेदना, संवेदनहीनता को दशार्या गया है। शोध छात्रा सुरभि शर्मा ने भी बैकबेंचर पर अपने विचार रखे। ज्योति किरन रतन के संचालन में अनंत बहादुर श्रीवास्तव की पुस्तकों जीव जागरण, साधना भक्ति पथ, स्तुति प्रतीति, स्मृति बोध संस्मरण का लोकार्पण भी मंच पर हुआ। शाम को महिला दिवस पर महिला राज्य और धर्म विषय पर हुये परिसंवाद के संग काव्यपाठ में तस्वीर नकवी, विमल किशोर, कमला गौतम, ऊषा राय, शांतम, आकांक्षा आजाद आदि सम्मिलित हुए। मैक्स हास्पिटल के स्वास्थ्य शिविर का भी पुस्तक प्रेमियों ने लाभ लिया।

सामाजिक कहानियों के इर्द गिर्द बुनी कुछ अच्छी वेबसिरीज

अभी तक आपको 100 प्रतिशत शुद्ध वेब सीरीज दोपहियों, मिजापुर , 'गुल्लक' और 'पंचायत' का नाम याद होगा । सब के सब लाजवाब कहानी और अपने देहाती फामूर्ले पर फिट बैठी और हिट रही । लेकिन बीच-बीच में ऐसी कई सीरीज बनी हैं, जिसे आप पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं । बीते दिनों हमने सूरज बड़जात्या की पहली सीरीज बड़ा नाम करेंगे के बारे में सुना , अब हम 3 और फैमिली सीरीज के बारे में चर्चा कर सकते है जिनकी रेटिंग भी हाई रही है । गुल्लक' और 'पंचायत' जैसी वेब सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं । इनके तीनों ही सीजन की रेटिंग काफी अच्छी है । दोपहिया का एक सीजन आ चुका है बाकी का फैंस बेसब्री से इसके अगले सीजन का इंतजार कर रहे हैं । इस इंतजार के बीच आप अन्य सीरीज को एन्जॉय कर सकते हैं । उनमें 'कोटा फैक्ट्री' सबसे आगे है । इसके भी 3 सीजन आ चुके हैं । इस सीरीज के लिए जितेंद्र कुमार को आईफा 2025 में बेस्ट डिजिटल एक्टर का अवॉर्ड मिला है. इसके तीसरे सीजन को पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में लेंस से फिल्माया गया है । इसके अलावा, सोनी लिव पर आई 'निर्मल पाठक की घर वापसी' भी एक अच्छी वेब सीरीज है, जिसे आप फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं । सीरीज में वैभव तत्ववादी ने लीड रोल निभाया । 5 एपिसोड की यह सीरीज सोनी लिव पर स्ट्रीम हुई । निर्मल पाठक की घर वापसी' की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है. सीरीज की कहानी एक निर्मल नाम के लड़के की है, जो बरसों बाद अपने पेरेंट्स के बिना अकेले गांव जाता है इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग हैं. फैंस इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजा कर रहे हैं । वहीं, वेब सीरीज 'एस्पिरेंट्स' भी एक अच्छी सीरीज है. साल 2021 में इसका पहला सीजन यूट्यूब पर आया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखने जाने वाला शो बना था। इसका दूसरा सीजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ. इसकी भी 9 आईएमडीबी रेटिंग है. इसके दो स्पिन ऑफ 'संदीप भैया' और 'एस के सर' की क्लास बन चुके हैं ।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

जलवायु कार्य योजना की अनदेखी

फरवरी के अंत से मार्च के प्रथम सप्ताह तक मौसम विभाग के अली में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के तीन हजार मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के संकेत दिए गए थे। लेकिन इसके बाद जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी उसमें गैर-जिम्मेदारी सामने आई है। उदाहरणार्थ-उत्तराखंड में सीमा क्षेत्र के पहले गांव माणा में सड़क चौड़ीकरण में लगे 55 मजदूरों का हिमस्खलन की चपेट में आना। वे बर्फ के नीचे दब गए। हेली सेवाओं, आईटीबीपी और सेना के 200 जवानों द्वारा 44 लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया जा सका । यदि मौसम विभाग द्वारा बनाई गई सावधानियों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए इतने लोगों को बचाने में जो ऊर्जा खर्च हुई है और आठ लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई, उन्हें भी बचाया जा सकता था। बद्रीनाथ के पास स्थिति माणा बाइ पास के निर्माण में लगे मजदूरों को इस दौरान छुट्टी दे देनी चाहिए थी क्योंकि इस दौरान हजार फीट की ऊंचाई पर मजदूरों के रहने लायक स्थितियां नहीं हैं और उनसे काम भी नहीं करवाया जा सकता। वर्ष-2021-24 के बीच जहां आस-पास हिमस्खलन की घटनाएं हो चुकी है। केदारनाथ में 2013 की आपदा के बाद से चोराबाड़ी ग्लेशियर से हिमस्खलन की घटनाएं थम नहीं रही हैं। माणा में जहां मजदूरों को रात में रहने की व्यवस्था थी वहां पर पहले भी हिमस्खलन हुआ है। ध्यातव्य है कि वर्षा और बर्फबारी का साय बिल्कुल बदल चुका है जिससे ग्लेशियरों की सतह कमजोर पड़ चुकी है। शीतकाल के समय तापमान बढ़ रहा है। दिसंबर जनवरी में दोपहर के समय केदारनाथ जैसे ऊंचाई बाले क्षेत्र में तापमान 12-16 डिग्री तक दर्ज किया गया है। पिछले वर्षों में जनवरी में दोपहर में तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया है। यही स्थिति केदारनाथ यमुनोत्तरी, बद्रीनाथ के ग्लेशियरों की है जिसके कारण बेमौसमी बर्फ के पिघलने की गति बढ़ती जा रही है।

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. मनीष मेहता के अनुसार दिसंबर-जनवरी में गिरने बाली बर्फ शुल्क होती थी जिससे हिमस्खलन कम होता था और यह बर्फ पिघलाने की गति को भी

कम करता था लेकिन कुछ वर्षों से मौसम में बदलाव होने से नवम्बर जनवरी तक बर्फबारी कम हो गई है। फरवरी मार्च में पड़ने वाली बर्फ बढ़ते तापमान के कारण जम नहीं पाती है। माणा में हिमस्खलन का कारण भी यही बताया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से बद्रीनाथ के ग्लेशियरों से लगातार एवलांच की घटनाएं हो रही हैं।

भू-वैज्ञानिक एस.पी. सती ने 2021 में चिपको नेत्री गौरा देवीके गांव रैली के निकट हिमस्खलन की घटना के बाद इस घाटी के संवेदनशील बर्फ वाले इलाके चिन्हित किए गए थे जहां हिमस्खलन की आशंका है। माणा के पास मजदूरों का शिविर भी इसी तरह के क्षेत्र में स्थित था। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । पुराने समय में यहां मानवीय आवाजाही कम थी। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में बर्फ की चोटियों मे कंपन न हो, इसलिए मंदिर में शंख नहीं बजता था लेकिन अब इसी क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के ता ह ता सड़क निर्माण में तेज ध्वनि करने वाली जेसीबी मशीनों का प्रयोग हो रहा हैं। अंधाधुंध हेली सेवाएं जारी हैं। जलवायु नियंत्रित करने वाले वनों का तेजी से क्षरण हो रहा है, जिसका ग्लेशियरों पर सीधा. प्रभाव पड़ रहा है। बद्रीनाथ में नीलकंठ, नर नारायण, कंचन गंगा, सतोपंथ, माणा और कुबेर पर्वत स्थित है। अन्य चोटियां भी हैं, जो बर्फ से ढकी रहती हैं।

यहां जो निर्माण हो रहा है उसका प्रभाव बढ़ते तापमान से साफ नजर आ रहा है। लोग कहते हैं कि सदियों पूर्व बद्रीनाथ मंदिर का जब निर्माण हुआ तो स्थानीय और लोक विज्ञान के पहलू को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाया गया था। इसी दौरान गंगोत्री के पास हर्षिल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शीतकाल यात्रा का संदेश देने के लिए पहुंचना था जिसे मौसम के कारण 6 मार्च के लिए बदला गया। हिमाचल में भी भारी भूस्खलन के चलते 480 सड़क बंद रहीं। जगह-जगह पर आठ लोगों की मौत हुई। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित होने के कारण हजारों लोग फंसे रहे। जलवायु परिवर्तन की ऐसी घटनाएं भविष्य में और बढ़ सकती हैं। इसलिए साल भर में जलवायु का कैलेंडर बनना चाहिए। पेड़-पौधे, जीव-जंतु, जल संरक्षण की दिशा में प्रयास करने होंगे। शीतकालीन सैलानी, पर्वतारोही मौसम की अनदेखी न करें । मनुष्य को अपने लालच भरी योजनाओं पर नियंत्रण करके प्रकृति को बचाने की दिशा में एकजुट प्रयासों को महत्त्व देना होगा ।

निजी डेटा सुरक्षा सुनिश्चित हो

डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा निजता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के समय में निजता के उल्लंघन को लेकर लोगों की चिंता उचित ही है। अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि ऐसे परिदृश्य में विकासशील देशों में न्यायपालिकाओं के लिए डिजिटल अधिकारों, मध्यस्थ दायित्व और ऑन लाइन प्लेटफार्मों के सरकारी विनियमन की सीमाओं की व्याख्या और परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। केन्याई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि दुनिया भर की न्यायपालिकाएं गोपनीयता, निगरानी, एआई नैतिकता और उभरती प्रौद्योगिकियों के शासन के आसपास के जटिल कानूनी सवालों से जूझती रहेंगी। वास्तव में तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण ने डेटा गोपनीयता को आवश्यक लक्ष्य बना दिया है। एक ऐसे देश के लिए जो इंटरनेट उपयोगकताओं की संख्या के मामले में शीर्ष तीन में है, एक उपयुक्त गोपनीयता कानूनी ढांचे की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न संस्थाओं के साथ साझा किए जा रहे व्यक्तिगत डेटा की मात्रा के साथ, यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत उपयोगकताओं को अपने व्यक्तिगत डेटा पर स्वायत्तता और नियंत्रण मिले।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करने के लिए मजबूत और संरचित गोपनीयता व्यवस्था की आवश्यकता को समझा है । इसने मसौदा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया और वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा इसका विश्लेषण किया जा रहा है। जेपीसी ने सिफारिश की है कि भारत में डेटा संरक्षण विधेयक के दायरे को डेटा के डिजिटलीकरण और स्थानीयकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विस्तारित करने की आवश्यकता है। हालांकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के नियम तय किए गए हैं। कुल मिलाकर व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए, डेटा संरक्षण कानूनों का पालन करना चाहिए और डेटा सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और इस्तेमाल वैधानिक आधार पर होना चाहिए जिसका इस्तेमाल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। व्यक्तिगत डेटा को उस उद्देश्य से ज्यादा समय तक नहीं रखा जाना चाहिए जिसके लिए इसे एकत्र किया गया था । कुल मिलाकर एक मजबूत गोपनीयता व्यवस्था स्थापित करके डिजिटल दुनिया में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

दो महासमाधियां

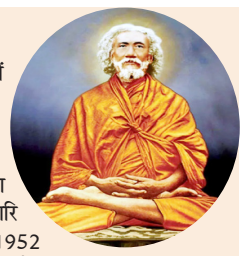

एक दिव्य गुरु को गुरु होने के लिए अपने शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। आध्यात्मिक गौरव ग्रन्थ, योगी कथा मृत के लेखक श्री परमहंस और अबाधित पुस्तक, कैवल्य दर्शनम-के लेखक श्रीश्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि आज भी अपने करोड़ों भक्तों के इस कथन को चरितार्थ करते हैं। मार्च माह में दोनो गुरुओं की गौरवपूर्ण महासमाधि (मृत्यु के समय एक योगी का अपने शरीर से अभिज्ञ अंतिम प्रस्थान) का प्रतीक है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि ने 9 मार्च, 1936 और विश्व प्रसिद्ध शिष्य परमहंस योगानन्द ने प्रभात, 1952 को महासमाधि में प्रवेश किया। क्रियायोग परंपरा के दोनों गुरुओं ने अपने शरीरों का एक पह चान योग्य वस्त्र की भांति परित्याग कर दिया। और योग प्राप्ति हेतु अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए विराट क्रिया श्वास के माध्यम से विलीन रहे। जैसा कि योग कथा मृत में वर्णित है क्रियायोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक श्वास क्रिया रक्त को कार्बन डाई आक्साइड से मुक्त करती है। और शरीर के रखरखाव को कम करती है। ऑक्सीजन के परमाणु कोशिकाओं को शुद्ध ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया से सेकंड को एक श्वास प्रक्रिया के द्वारा उतना ही आध्यात्मिक विकास होता है जितना प्राकृतिक विकास के माध्यम से एक वर्ष में होता है।

क्रियायोग एक प्राचीन विज्ञान है जिसे कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था और बाद में पतंजलि और अन्य शिष्यों को इसका ज्ञान था वर्तमान युग में इसे बाबा जी ने लोहिड़ी को प्रदान किया था जिन्होंने इसे योगानन्द के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरि को प्रदान किया था। संन्यास के पूर्व योगानन्द का नाम मुकुन्द था। 1920 में जब वे 17 वर्ष के थे, उनको मैट अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरि से हुई थी। वे अपने गुरु के कठोर आचरण-दर्शन-जिसके कारण आश्रम के अन्य शिष्य मधुर शब्दों की खोज में आश्रम छोड़कर चले जाते थे में मुकुन्द की आध्यात्मिक शुरूआत के निर्देश ग्रहण किये। मुकुन्द को उनके गुरु द्वारा एक गुरु बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। क्योंकि महावतार बाबा जी के अनेक वर्ष पूर्व स्वामी युक्तेश्वर गिरि से स्पष्ट रूप से यह कहा था कि-पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रचार करने के लिए योगानन्द जी का चुनाव किया गया है। प्रारम्भ में तो योगानन्द जी पूर्व में भी किसी संस्था की स्थापना करने के इच्छुक नहीं थे। परन्तु उन्होंने अपने गुरु के आगे सिर झुकाकर समर्पण कर दिया। उन्होंने सन् 1917 में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थापना की। सन् 1920 में उन्हें अमेरिका से बुलावा आया जिसकी भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। युवा गुरु उस देश की भाषा पर निकल पड़े जिसकी भाषा से वे उतने अनभिज्ञ थे जितने कि उस देश के लोग योग से। परंतु भाषा की यह समस्या ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त गुरु का मार्ग रोकने में असफल रही। वे जिस जहाज से यात्रा कर रहे थे। उसपर उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना पहला व्याख्यान दिया था। बाद में अमेरिका के प्रत्येक शहर में खचा-खच भरे सभागारों में व्याख्यान देने के लिए ईश्वर ने उनका चयन किया। उसके परिवार स्वरूप सन-1920 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप (एस आर एफ) की स्थापना की। अद्वितीय गुरु ने महा समाधि में प्रवेश करने तक संन्यासियों और क्रिया योग को शिक्षा प्रदान की। उनकी महासमाधि भी एक अद्भुत घटना थी। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। शव ग्रह के निदेशक हैरी हो. रोवे ने यह लिखा है कि- परमहंस योगानंद की देह निर्विकारिता की अद्भुत अवस्था में थी। महान गुरु अपने जीवन काल के समान ही मृत्यु में भी मानव जाति के सम्मुख यह प्रमाण प्रस्तुत कर रहे थे कि योग और ध्यान के माध्यम से प्रकृति और समय की शक्तियों पर नियंत्रण पाना संभव है।

बांग्लादेश में लोकतंत्र के हालात चुनौतीपूर्ण

इस समय बांग्लादेश बदलावों और आशंकाओं के दौर से गुजर रहा है। देश को वैधानिक ढांचा अस्त-व्यस्त हो गया है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तियां हावी हो गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण बांग्लादेश में असहमति और राजनीतिक संघर्ष का दायरा व्यापक रूप से फैला हुआ है जो राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्राक्रिया के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।

कथित इस्लामिक राष्ट्रवाद की स्थापना, जातीय संघर्ष, राजनीतिक असहमति, वैधानिक व्यवस्थाओं में अपारदर्शिता तथा भेदभाव, विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने की परंपराएं और सत्तारूढ़ पार्टी का अधिनायकवाद जैसे मुद्दे बांग्लादेश की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि इसके नेताओं का विश्वास संसदीय परंपराओं और चचाओं में कम रहा है। सैन्य और शक्तियों से अभिशप्त इस देश में पक्ष-विपक्ष के नेताओं में गहरा अविश्वास और असहमति होती है। सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देती है। लिहाजा देश में पक्ष-विपक्ष के बीच सड़कों पर शक्ति संघर्ष होता है जिससे समूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित रहती है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा बढ़ती है। पिछले वर्ष शेख हसीना के विरोध को विपक्ष का व्यापक समर्थन हासिल हुआ था और इसमें प्रमुख भूमिका छात्रों के समूह स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की थी। अब इसी छात्र समूह ने नई राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटिजन पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में हाथ आजमाने की घोषणा की है। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन समूह ने सिविल सेवा नौकरी कोटा के खिलाफ बांग्लादेश में व्यापक अभियान चलाया था। युवाओं को इस छात्र समूह को व्यापक समर्थन प्राप्त है। और यही इसकी असल ताकत है।

नाहिद इस्लाम ने नई राजनीतिक पार्टी का प्रमुख उद्देश्य दूसरे गणराज्य की स्थापना को बताया है। एक गणराज्य के रूप में बांग्लादेश का संविधान आदर्श माना जाता है। जहां सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार होता है। नाहिद इस्लाम के दूसरे गणराज्य की स्थापना के दावों से डर आशंकाओं को बल मिल सकता है कि कहीं वे इसे शरिया कानून पर आधारित इस्लामिक देश तो नहीं बनाना चाहते हैं। स्मरणीय है कि- शेख मुजीब-उर-रहमान ने एक राष्ट्र राज्य के रूप में बांग्लादेश की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता पर रखी थी। इस समय बांग्लादेश में पाकिस्तान को दुश्मन माना जा रहा है। बांग्लादेश की कई राजनीतिक पार्टियां मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका पर सवाल उठा रही हैं। नेशनल सिटिजन पार्टी का नेतृत्व कर रहे नाहिद इस्लाम ने जिस नए बांग्लादेश को स्थापित करने का वादा किया है। उसमें भारत और पाकिस्तान का समर्थन जैसे मुद्दों को गौण रहने की बात कही है। यदि नाहिद वास्तव में मध्यमार्ग की राजनीति करना चाहते हैं तो उन्हें कट्टरपंथी ताकतों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्हें तालिबान की तर्ज पर छात्र राजनीति करने से बचना होगा।

नाहिद इस्लाम भारत का समर्थन भले ही न करें लेकिन यदि धर्मनिरपेक्षता और समावेशी व्यवस्था पर आधारित बांग्लादेश के निर्माण की ओर बढ़ते हैं तो यह सब के दिल में होगा। बांग्ला देश में किसी मध्यमार्गी राजनीतिक दल की जरूरत लगातार महसूस को जा रही थी। क्योंकि वर्तमान राजनीतिक दल अपनी नीतियों के कारण विवादित रहे हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित भी करते रहे हैं। प्रमुख पार्टी आवामी लीग ने धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद के चार स्तंभों पर आधारित पार्टी की राजनीतिक विचारधारा ने 1971 में देश के पहले संविधान में निहित सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा धर्मनिरपेक्ष और समावेशी बांग्लादेश की स्थापना के लिए मंच तैयार किया लेकिन आगे चलकर इस पार्टी की नेता शेख हसीना ने सत्ता पर शिकंजा बनाए रखने की राजनीति को भी पोषित किया जो उनके विरोध और सत्ता खोने का प्रमुख कारण बना। बंग्लादेश की राजनीति आशंकाओं से ग्रस्त रही है। और सत्तारूढ़ पार्टियों ने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया। इस नीति को लगातार आजमाया गया। आवामी लीग की नेता शेख हसीना के कार्यकाल में प्रमुख विपक्षी दल के नेता नजरबंद रखे गए या उन्हें जेल में डाल दिया गया था। कुछ गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए थे। इस दौरान बीएनपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी जेल में थी और वे चुनाव मैदान में थीं ही नहीं। लिहाजा, पिछले आम चुनावों में एक बार फिर आवामी लीग की नेता शेख हसीना का देश का प्रधानमंत्री बनना तय होगया था। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएन की) के अधिक-ांश दलों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया।

मजेदार बात यह कि ये आम-चुनाव तत्कालीन प्रधान मंत्री शेख हसीना की देखरेख में ही कराए गए थे और उन्होंने किसी अंतरिम सरकार की देख रेख में आम चुनावों की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया था। बांग्लादेश के एक और प्रमुख राजनीतिक दल बीएनपी को रुढ़िवादी दला माना जाता है जो दक्षिणपंथी दलों को एकजुट करता रहा है। इसे भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। बीएनपी के कार्यकाल के दौरान सत्तावादी ताकतों को मजबूती मिली और शेख हसीना को जेल में डाल दिया गया था। रुढिवादी और इस्लामिक व्यवस्था कायम करने के लिए प्रतिबद्ध जमात-ए-इस्लामी नामक राजनीतिक दल का भी बांग्लादेश के बहुसंख्यक इस्लामी समाज पर गहरा प्रभाव है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ था। जमात एक तरह से स्वतंत्र बंग्लादेश का विरोध करता रहा है।

भाजपा : दक्षिण में सेंध लगाने के लिए उतावली

कल्पना कीजिए कि इस सोच की कितनी संभावना है, खासकर जब भाजपा दक्षिण भारत में अपनी जगह बनाने के वास्ते कड़े प्रयास कर रही है। क्या विजयन और नरेन्द्र मोदी केरल में कांग्रेस को खत्म करने के वास्ते सच में एकजुट हो सकते हैं, भले ही यह पूरी तरह से पर्दे के पीछे हो ? इस विचार को जरा यहीं थामकर रखें, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है।

राजधानी दिल्ली समेत, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में जीत हासिल करने के बाद- हिमाचल प्रदेश की चार सीटें अपने पास होने और पंजाब की 13 सीटों पर अगली नजर के साथ- उसे पता है कि अब दक्षणी मोर्चे में भी सेंध लगाना जरूरी है। कुछ समय से तमिलनाड़ पर ध्यान केंद्रित होने की वजह से जाहिर है केरल में विस्तार पर जोर कम रहा। केरल के सर्वप्रिय गुरुवायूर मंदिर गृहक्षेत्र त्रिशूर से पिछले साल पूर्व अभिनेता सुरेश गोपी ने लोकसभा सीट जीतकर भाजपा के खिलाफ रही केरल की वर्जना को तोड़ा था। पार्टी का मानना है कि नायर समुदाय, जो कभी वामपंथियों की रीढ़ हुआ करता था, बहुत जल्द उसकी तरफ झुक जाएगा। भाजपा अपनी इन उम्मीदों में गलत नहीं है। यहां तक कि पिछले कुछ दशकों से केरल के मध्यवर्ग को कट्टर वामपंथी होने के बावजूद पास के मंदिर में जाकर दीया जलाने में कुछ भी गलत नहीं दिखता। बड़ी समस्या, जाहिर है, यह है कि भाजपा के पास अभी भी राज्य में नेतृत्व करने के लिए कोई उचित चेहरा नहीं है- पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंदशेखर काफी पढ़े-लिखे हैं और थरूर से तिरुवनतपुरम छीन भी सकते थे, सिवाय इसके कि उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसलिए जब चार बार के कांग्रेस सांसद ने पिछले हुफ़्ते कहा अगर पार्टी मेरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है. तो मैं बना रहंगा, अगर नहीं, तब मेरे पास दूसरे विकल्प हैं , तो पूरे देश में चटपटी राजनीतिक चर्चा छिड़ गई तो क्या थरूर कांग्रेस छोड़कर भाजपा या वामपंथ में शामिल होंगे? क्या वे कांग्रेस के भीतर ज्यादा जगह बनाने को कसमसा रहे हैं । उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनुने की खातिर दबाव डालना? ऐसे में केरल की तिकड़ी- प्रियंका गांधी, राहुले गांधी और वेणुगोपाल - क्या थरूर को मनाने में भूमिका निभाएगी ? क्या संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक भारतीयता के आकर्षण को त्यागकर न्यूयॉर्क वापस लौट जाएंगे, और अपनी 30वीं किताब लिखेंगे ? तथ्य

यह है कि भले ही केरल में थरूर की जमीनी पकड़ रमेश चेन्निथला, वीड़ी सतीसन और केसी वेणुगोपाल जैसे नेताओं जितनी मजबूत न हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर वे ही हैं, न कि ये तीनों- वेणुगोपाल भी नहीं, हालांकि, उन्हें गांधी परिवार का मजबूत समर्थन हासिल है। बेशक, यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर रामचंद्र गुहा जैसे बुद्धिजीवी थरूर का समर्थन कर रहे हैं, तो केरल में भी जमीन थोड़ी बदल सकती है। बिना शक यह दलील सबको पता है।

यह उस व्यक्ति का साथ देने जैसा है जो ठंडे मुल्क से केवल 2009 में आया और फिर भी चार बार लोक-सभा सीट जीतने में सक्षम रहा यह उपलब्धि कोई छोटी नहीं है। इसके अलावा थरूर वेणुगोपाल नहीं हैं, जिनके सिर पर ईश्वर का वरदहस्त है। निश्चित रूप से, कांग्रेस को प्रथम परिवार की सख्त पकड़ से ढीला करना होगा, जो पार्टी की रोजाना की राजनीति की हर करवट और हरकत का दम घोंट रही है। शशि थरूर की महत्वाकांक्षा भले ही उनको प्रभावशाली ईसाई एवं हिंदू समुदायों का समर्थन हासिल न हो इस और एक स्वस्थ कदम है इसी बीच, भाजपा दिनो-दिन अपना भारी-भरकम विजयरथ विन्ध्य पर्वतमाला के पार ले जाने में जोर लगा रही है।

आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा इतनी खुश क्यों है। राजधानी दिल्ली समेत, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में जीत हासिल करने के बाद उसे पता है कि अब दक्षिणी मोर्चे में भी सेंध लगाना जरूरी हो रहा है । मध्यवर्गीय भारत का बिगड़ैल लाल यानी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों एक लघु तूफान में फंसे हुए हैं, और यह सब इंडियन एक्सप्रेस के साथ 45 मिनट के पॉडकास्ट में मलयालम में उनके कहे चार शब्दों वाले एक वाक्य की वजह से है मैरे पास दूसरे विकल्प हैं। चार बार के सांसिद थरूर 2009 में किए गए अपने ट्वीट मैं हमारी सभी पवित्र गायों का साथ देने के लिए कैटल क्लास में यात्रा करने जा रहा हूं, जिसने मितव्ययिता

के नारे के इर्द -गिर्द घड़े पाखंड के असामान्य प्रदर्शन पर तंज कर देश को खूब हंसाया था, उस वक्त के बाद से वे एक लंबा सफर तय चुके हैं हालांकि, खुद सोनिया गांधी ने ऐसी शब्दावली के लिए उनकी ताड़ना की थी। हो सकता है थरूर की टिप्पणियों पर उठा नवीनतम विवाद भी सप्ताहांत तक ठंडा पड़ जाए, खासकर जब केरल कांग्रेस के नेताओं और पार्टी आलाकमान के बीच 2026 में केरल के आगामी चुनाव को लेकर होने वाली तैयारी बैठक होगी, और सांसद की आहत हुई भावना को शांत करने का प्रयास किया जाए । पार्टी के सभी गटों के बीच एकता दिखाने की बात पहले ही कही जा रही है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, वहां से पूर्व सांसद और उनके भाई राहुल गांधी और कांग्रेस संगठन के प्रभारी महासचिव और अलपुझो से. सांसद केसी वेणुगोपाल इस पुरानी पाटी में सबसे शक्तिशाली तिकड़ी- निश्चित रूप से अपने चुनावी अभियान की अगुवाई इस पेशकारी से करेंगे भगवान के अपने देश में सब ठीक है और कांग्रेस अगले साल सत्ता में वापस आएगी। सिवाय इसके कि दक्षिषणी राज्य में मंथन चल रहा है और अरख सागर की फि जां इन दिनों कुछ बदली-सी है। पिछले हफ्ते कोचीन में हुए निवेशक शिखर सम्मेलन में भाजपा नेता पीयूष गोयल और केरल के मुख्यमत्री और सीपीआई (एम) नेता पिनाराई विजयन को दिल खोलकर हंसते हुए देखा गया। कुछ ही दिनों बाद, सीपीएम ने केरल की अपनी सभी पार्टी इकाइयों को एक नोट भेजा, जिसमें बताया गया कि पार्टी मोदी सरकार को फासीवादी या नव-फासीवादी क्यों नहीं बता रही । इसमें कोई संदेह नहीं कि यह टिप्पणी गत 6 मार्च को कोल्लिम में होने जा रहे सीपीएम के 24वीं पार्टी सम्मेलन में बहस के केंद्र में होगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह पार्टी में शक्तिशाली प्रकाश करात गुट द्वारा अपनाई कांग्रेस विरोधी नीति की वापसी है- पिछले सितंबर में सीताराम येचुरी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद, जिन्होंने हमेशा विपक्षी एकता के लिए जोर दिया और मानते थे कि कांग्रेस पार्टी इसका धड़कता दिल है इसलिए इन दिनों केरल में थरूर की महत्वाकांक्षाओं से बड़ा सवाल यह है कि क्या वामपंथी भाजपा के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं? और क्या वे कोल्लम पार्टी सम्मेलन में भाजपा को नहीं, बल्कि कांग्रेस को वामपंथ का मुख्य राजनीतिक दुश्मन बताने की ओर लौटेंगे यह सब इसलिए क्योंकि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूड-ीएफ इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है ?

तो कल्पना कीजिए कि इस सोच की कितनी संभावना है, खासकर जब भाजपा दक्षिण भारत में अपनी जगह बनाने के वास्ते कड़े प्रयास कर रही है। क्या विजयन और नरेन्द्र मोदी केरल में कांग्रेस को खत्म करने के वास्ते सच में एकजुट हो सकते हैं, भले ही यह पूरी तरह से पर्दे के पीछे हो ? इस विचार को जरा यहीं थामकर रखें, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है।

घूँघट की बगावत

16 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

अपने समाज, अपनी व्यवस्था, के विरुद्ध सामूहिक अविश्वास का मौन प्रदर्शन

भारत कोई गरीब देश नहीं, लेकिन कुव्यवस्था से बेहाल है। अन्यथा उच्च मध्यवर्गीय भारतीयों के पास जितना धन है वह अनेक यूरोपीय देशों में नहीं दिखता, लेकिन हमारी आम राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक व्यवस्थाएं बेहाल हैं, जो हतोत्साहित करती हैं। ये व्यवस्थाएं योग्यता या विवेक का आदर नहीं करतीं। शैक्षिक संस्थाएं या तो खानापूरी या शुद्ध धंधा हैं। सो, प्रतिभाएं रामभरोसे रहती हैं।

अन्य क्षेत्रों में भी प्रायः हर अवसर या पद किसी अन्य आधार पर देने-लेने की व्यवस्था स्थापित है। इसीलिए लोग विदेश पलायन कर रहे हैं, जहां समुचित अवसर और सम्मान मिलने की आस हो। इसे लोगों का लालच कहना उनका अपमान करने जैसा है। स्वतंत्र भारत ने ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसमें अपनी कोई कल्पना नहीं है। इसीलिए वह सद्गुण, प्रतिभा और योग्यता से बेपरवाह है। अमेरिका ने ऐसी व्यवस्था बनाई, जो सारी दुनिया से गुण, प्रतिभा और योग्यता का स्वागत करती है। अभी सारा आक्रोश अमेरिका से अवैध भारतीयों को भेजने के तरीके पर दिखाना ऐसा है, मानो उन्हीं भारतीयों को राहत देने के लिए यहां कोई परवाह हो। वस्तुतः हमारा बड़बोलापन और निकम्मापन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तेवर से हम शेखी बघारते या दूसरों की निंदा करते हैं, उसी रौ में हर जिम्मेदारी किसी अन्य पर डालकर अपना पल्ला झाड़ते हैं।

सुरक्षा से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, दैनिक प्रशासन और न्याय व्यवस्था तक हर मामले में पार्टीबाजी, पर-दोषारोपण और लफ्फाजी हमारा प्रमुख विमर्श है। यह भारत में लंबे समय से चल रहा है। दूसरों को दोष देकर अपने को स्वतः पीड़ित, सही या श्रेष्ठ समझना। इसमें आसानी है। इसके लिए किसी ठोस परीक्षण का श्रम नहीं करना पड़ता। इस प्रक्रिया में द्वेष-निंदा-आरामपसंदगी की ऐसी तिहरी माया है कि हम सामने दिखते हाथी जैसा बड़ा सच भी अनदेखा कर देते हैं। अपने विमर्श में नियमित रूप से हम जो दावा करते हैं, वास्तविक व्यवहार उसके धुर विपरीत दिखाता है। हमारा संपूर्ण जीवन नेताओं से लेकर बुद्धिजीवियों, छात्रों और मैनेजरों तक यानी नीति, उद्योग, शिक्षा, कला, रहन-सहन, भाव-भंगिमा, खेलकूद, मनोरंजन आदि तक मुख्यतः विदेशी विचारों, वस्तुओं, भाषा, शैली, माडल आदि से प्रेरित संचालित है।

क्या यह साफ नहीं दिखाता कि हम अमेरिकी-यूरोपीय चीजों, विचारों, उपायों, पुस्तकों, फिल्म, संगीत और खेल आदि को भी श्रेष्ठतर मानते हैं? उसके लिए अपनी हर चीज, ज्ञान, दर्शन, यम-नियम, भाषा-संस्कृति यहां

अपवाद छोड़कर हमारे बुद्धिजीवियों में नीति-निर्माण और सुव्यवस्था की समझ तक नहीं रही है। वे नारेबाजी के भरोसे रहते हैं। तब कौन देश ऐसे लोगों की भीड़ चाहेगा? यह स्वाभाविक है कि अमेरिकी प्रशासन भी केवल सुयोग्य भारतीयों को रखना चाहे और बाकी को कड़ाई से बाहर करे। हमें अपना घर सुधारने की चिंता होनी चाहिए। दूसरों की निंदा करना आत्महीनता है।

तक कि सदा के लिए देश छोड़कर अमेरिका-यूरोप में बस भी जाना चाहते हैं? पूरी बुद्धि, परिश्रम और धन लगाकर बच्चों को वहां पहुंचाना और सेटल करना चाहते हैं।

यह व्यावहारिक बिंदु है। एक छोटा बच्चा भी सामने उपलब्ध दो चीजों में बेहतर उठाता है। अतः सत्य और व्यवहार को कसौटी बनाना ही उचित है। तब दिखेगा कि अधिकांश भारतीय अमेरिका-यूरोप को अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि हम अपना कुछ भी तुलनीय नहीं बना सके हैं।

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे या प्रवेश करने वाले भारतीयों को वहां से निकाले जाने पर हमारे देश में तमाम लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहां से लोगों को जिस तरह भेजा जा रहा है, उसका तौर-तरीका चुभने वाला है। इस बीच मूल बिंदु उपेक्षित है कि क्यों भारत से बड़ी संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं? आम समझ यही है कि लोग रोजगार के लिए जाते हैं, परंतु संपन्न घरों के युवा भी अमेरिका-यूरोप जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को यहां रोजी-रोटी की खास समस्या नहीं है। वस्तुतः अमेरिका या यूरोप जाने वाले भारतीयों में कम ही लोग वहां कोई नियुक्ति-पत्र लेकर जाते हैं। अधिकांश वहां पढ़ाई के लिए जाते हैं और फिर कोई छोटी-मोटी नौकरी शुरू करते हैं। कई बार यह वहां के नियमों का उल्लंघन करके होता है। कनाडा जाने वाले अधिकांश भारतीयों में तो कोर्स-दाखिला केवल बहाना होता है। वे वहां रह जाने की मंशा से ही जाते हैं। उसी प्रक्रिया का एक रूप यहां देश में भी दिखता है। गांव-गांव में असंख्य माता-पिता बच्चों को पढ़ाते हुए यही चाहते हैं कि वे बाहर निकल कर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि जगहों पर जाकर काम करें। जबकि दिल्ली-बेंगलुरु में बसे भारतीय अपने बच्चों के लिए यूरोप-अमेरिका जाकर रहने की आकांक्षा रखते हैं और वैसी योजनाएं बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पलायन के लिए चयन जैसी है। यह अपने समाज, अपनी व्यवस्था के विरुद्ध सामूहिक अविश्वास का मौन प्रदर्शन है। लोग अपने संसाधन, बुद्धि और परिश्रम लगाकर अपना समाज और देश छोड़कर वहां जाना चाहते हैं, जो अधिक व्यवस्थित और अवसर देने वाला लगता है। यही बिंदु विचारणीय है।

प्रश्न है कि यदि हमारे ऊपर भेदभाव, उपेक्षा, उत्पीड़न आदि कोई स्वदेशी करे-तो क्या वह मंजूर है? जबकि कोई विदेशी उसके विपरीत व्यवहार करे तो हमें नामंजूर होगा? इसी का उत्तर हमारे लाखों-लोग अवसर मिलते ही विदेश पलायन को प्राथमिकता के रूप में देते हैं। देश त्याग कर यूरोप, अमेरिका या आस्ट्रेलिया में जा बसने की उत्कट प्रकिया यही है।

यह उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा, उनका शासन खुशी-खुशी स्वीकार करने के सिवा और क्या है? इसके लिए वे कष्ट भी उठाते हैं। यानी न केवल वह संस्कृति और शासन बेहतर है, बल्कि उसमें प्रजा बनने के लिए लंबी तपस्या करने, वहां नागरिकता-विहीन रहकर भी जीवन लगाने के लिए तमाम भारतीय तैयार हैं। बिना किसी आमंत्रण या दबाव के।

इसका कारण मात्र लोभ को बताना उन भारतीयों का अपमान करना है, जिन्हें हम पहले तो उचित अवसर या स्थान नहीं देते, फिर उनकी चाह और परिश्रम का मजाक उड़ाते हैं। तथ्यों और प्रमाणों से बेपरवाह।

बिखराव के दौर से गुजर रही बसपा

जिस मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध बसपा का जन्म हुआ था, 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उसी ब्रह्मण समुदाय के समर्थन की जरुरत महसूस हुई तो तिलक, तराजू और तलवार जैसा नारा भी बदल गया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी, सर्वजन समाज की बातें करने लगी और यह नया नारा लगा हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। उस समय उत्तर प्रदेश में 37 प्रतिशत ब्राह्मणों ने पार्टी को वोट दिया था।

चार बार देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद अन्य सत्ताधीशों की ही तरह मायावती भी अहंकार के साथ साथ परिवारवाद का भी शिकार होती चली गयीं। कभी अपने को जिंदा देवी बतातीं तो कभी अपने भाई व भतीजे के मोह में डूबती नजर आतीं। कभी अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़तीं तो कभी उनपर पार्टी का टिकट बांटने में लोगों से करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप लगा। हद तो यह कि अपने जीवनकाल में ही मायावती ने बाबा साहब आंबेडकर व कांशी राम के साथ ही अपनी भी प्रतिमायें लगवा डालीं। जिसतरह कांशी राम को अपने परिवार से अलग उत्तराधिकारी के रूप में मायावती नजर आयी थीं उस तरह मायावती को परिवार से बाहर अपनी पार्टी का कोई योग्य नेता नजर ही नहीं आया। और आखिरकार मायावती के इन्हीं स्वार्थपूर्ण फैसलों के चलते उनकी पार्टी का जनाधार घटता चला गया। पिछले लोकसभा चुनावों से पूर्व जब इण्डिया गठबंधन वजूद में आया तो मायावती उस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनीं। उसी समय यह अंदाजा लगाया जाने लगा था कि मायावती भाजपा के प्रति नरम रुख अपना रही हैं। इसके पीछे के कारणों से भी अनेक राजनैतिक विश्लेषक बखूबी वाकिफ हैं। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने मायावती पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि यदि बीएसपी ह्यइंडियाह्ल गठबंधन में होती तो पिछले वर्ष हुये लोक-सभा चुनावों में एनडीए की जीत नहीं होती। इस आरोप से तिलमिला कर मायावती ने कांग्रेस को ही बीजेपी की ह्यबीह्ल टीम बता डाला। जबकि देश देख रहा है कि इस समय देश में सत्ता, भाजपा व संघ के विरुद्ध जितना राहुल गाँधी मुखर हैं उतना कोई नहीं जबकि मायावती के रवैये से तो पता ही नहीं चलता की वे विपक्ष में हैं या सत्ता के साथ?

सच तो यह है कि मायावती के नेतृत्व में बसपा का न केवल समाज में प्रभाव कम होता जा रहा है बल्कि संगठन भी बिखराव के दौर से गुजर रहा है। पिछले दिनों जिसतरह उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक समेत सभी मुख्य पदों से हटा दिया और दो दिन बाद ही उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया उससे भी यही सन्देश गया कि मायावती को अपने परिवार के बाहर भी कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आया और जिस भतीजे को अपना राजनैतिक उत्तराधिकारी बनाया भी उससे भी जल्द ही पीछा छुड़ा लिया? इस तरह के ढुलमुल फैसलों का प्रभाव निश्चित रूप से पार्टी पर जरूर पड़ेगा। सच तो यही है कि कांशी राम की विरासत के रूप में मिले व्यापक जनाधार वाले राजनैतिक दल को मायावती की तर्ज-ए-सियासत के चलते काफी नुक-सान हुआ है।

1980 के दशक में बसपा प्रमुख कांशी राम पूरे देश में घूम घूम कर भारतीय समाज को 85:15 का जनसँख्या अनुपात समझाते थे और यह बताते थे कि 15 प्रतिशत कथित उच्च जाति के लोग शेष 85 प्रतिशत जातियों व समुदायों के लोगों पर राज कर रहे हैं। और तभी यह नारा प्रचलित हुआ था ह्म वोट हमारा, राज तुम्हारा ह्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसे जैसे कांशी राम के नेतृत्व में यह बहुजन आंदोलन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मनुवाद तथा सनातन व्यवस्था में उल्लिखित वर्ण व्यवस्था पर इनका आक्रमण और तेज होता गया। यहाँ तक कि ह्यतिलक, तराजू और तलवार जैसा ह्यअभद्र नारा भी उन्हीं दिनों में खूब प्रचलित हुआ। यही वह आंदोलन था जिसमें दलित पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जुड़ते चले गये। यानी कांग्रेस का परम्परागत वोट बैंक धीरे धीरे खिस-काना शुरू हो गया। इसी बीच कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी नामक एक नये राजनैतिक दल की स्थापना कर दी। उसी दौरान कांशी राम की भेंट मायावती से हुई जोकि उस समय वकालत व बी एड करने के बाद दिल्ली इंद्रपुरी स्थित जेजे कॉलोनी में एक अध्यापिका के रूप में कार्यरत थीं और साथ ही सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थीं। तभी कांशी राम ने मायावती के तेज तर्रार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहा था कि ह्म ह्लमैं तुम्हें एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक नहीं बल्कि आईएएस अधिकारियों की पूरी कतार तुम्हारे आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी हो जाएगी। ह्व तभी से वे कांशी राम के सहयोगी के रूप में उनके साथ प्रायः देखी जाने लगीं तथा उनके ह्यक्रन्तिकारी ह्य व उत्तेजक भाषण भी लोगों को प्रभावित करने लगे।

कांशीराम का 9 अक्टूबर 2006 को 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कांशीराम के जीवन के अंतिम दौर में उनकी विरासत को लेकर बसपा के भीतर तथा कांश-ीराम के परिजनों के द्वारा काफी विवाद भी खड़ा किया गया। परन्तु तेज तर्रार मायावती तब तक कांशी राम पर व उनकी विरासत रुपी बसपा पर पूरा नियंत्रण कर चुकी थीं। यही वजह थी कि बौद्ध धर्म के अनुसार हुये कांशीराम के अंतिम संस्कार में उनके परिजनों ने नहीं बल्कि स्वयं मायावती ने ही उनकी चिता को अग्नि दी। अब पार्टी में उन्हें ह्यबहन जी ह्य के नाम से बुलाया जाने लगा। कांशीराम के नेतृत्व में ही बीएसपी ने 1999 के संसदीय चुनावों में 14 संसदीय सीटें जीतीं थीं। मायावती को चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठने का भी सौभाग्य हासिल है। परन्तु यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस बसपा को कांशीराम ने एक मिशन के रूप में स्थापित किया था और कांशी राम के जिस मिशन से बड़े सामाजिक परिवर्तन की आहट महसूस हो रही थी, पार्टी पर मायावती का वर्चस्व होने के बाद वही मिशन, वही पार्टी अब सत्ता, वैभव, आत्ममुग्धता और परिवारवाद का शिकार होती नजर आने लगी। यहाँ तक कि केवल सत्ता हासिल करने के लिये बुनियादी विचारों से भी समझौता करने लगीं। जिस मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध बसपा का जन्म हुआ था, 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उसी ब्रह्मण समुदाय के समर्थन की जरुरत महसूस हुई तो तिलक, तराजू और तलवार जैसा नारा भी बदल गया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी, सर्वजन समाज की बातें करने लगी। और यह नया नारा लगा हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। उस समय उत्तर प्रदेश में 37 प्रतिशत ब्राह्मणों ने पार्टी को वोट दिया था।

मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के बावजूद हमारे उद्योग चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहे

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका भी उल्लेख किया कि बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। उन्होंने छह करोड़ से अधिक एमएसएमई के लिए कर्ज वितरण के नए तरीके विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। ऐसा किया ही जाना चाहिए, लेकिन यह समझा जाए तो बेहतर कि इन उद्यमों की समस्या कर्ज लेने में कठिनाई नहीं है। हमारे उद्योग ऐसे उत्पाद भी नहीं बना पा रहे हैं, जो उच्च तकनीक आधारित हों और जो अपेक्षाकृत महंगे हों। वे अपने उत्पादों को विश्वस्तरीय बना पाने में इसलिए नाकाम हैं, क्योंकि अनुसंधान एवं विकास पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं कर रहे हैं। विडंबना यह है कि जो कारोबारी आर्थिक रूप से सक्षम हैं और

अनुसंधान एवं विकास पर आसानी से पैसा खर्च कर सकते हैं, वे भी ऐसा करने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। चूंकि अधिकांश एमएसएमई अनुसंधान एवं विकास पर अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं, इसलिए सरकार को ऐसा कोई तंत्र बनाना चाहिए, जो एमएसएमई के लिए यह काम करे और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में सक्षम बनाए। इससे ही उनके उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा और यह कहा जा सकेगा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि इंजन बन गया है। सरकार को ऐसे औद्योगिक क्षेत्र बनाने चाहिए, जहां पर उद्योगों के लिए वह सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इस मामले में पूर्वी एशियाई देशों से सीख लेने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों अर्थात एमएसएमई को लेकर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि उद्योगों को अनुसंधान एवं विकास का उपयोग करके ऐसे उत्पादों के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, जिनकी विदेश में मांग है, लेकिन आखिर ऐसा कब होगा? उचित यह होगा कि यह जानने की कोशिश की जाए कि भारतीय उद्योग यह काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

यह जानना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि तमाम अनुकूल परिस्थितियों के साथ देश में सस्ता श्रम भी उपलब्ध है। इस तथ्य को ओझल नहीं किया जाना चाहिए कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद भी चीन विश्व का कारखाना बना हुआ है। हमारे उद्योग चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अब कई पूर्वी एशियाई देश विश्व व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। एक तरह से अब भारतीय उद्योगों को उनसे मुकाबला करना पड़ रहा है। यह ठीक नहीं। भारतीय उद्योग उस गुणवत्ता के उत्पाद नहीं बना पा रहे हैं, जिनकी विश्व बाजार में मांग हैं। भारतीय उद्योग अपने उत्पादों की गुणवत्ता के मामले में ही नहीं पिछड़ रहे हैं, बल्कि उनकी उत्पादन लागत भी अधिक है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com